www.tamsasanket.com
वर्षः 06 || अंक 139 || लखनऊ
बुधवार
19 अगस्त 2026 || पृष्ठः 04 || मूल्यः ₹2
आज़ादी का अमृत महोत्सव
दैनिक
तमसा संकेत
https://epaper.tamsasanket.com
लखनऊ व अम्बेडकर नगर से एक साथ प्रकाशित
» डॉ. लोहिया की जन्म भूमि से सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र
मौसम
सूर्योदयः 05:40
सूर्यास्तः 06:40
अधिकतमः 33°00
न्यूनतमः 28°00



पेज 07

विशेष समाचार
नितिन नवीन की नई टीम ... >>पेज 04
लंबित मांगों पर भारतीय ... >>पेज 06
सुशांत केस के बाद रिया के पिता की ...

योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में योगी ने कहा- पीआरडी जवानों को सुविधा मिली है तो उन्हें और बेहतर ढंग से काम करना होगा। हम सब भारतवासियों का एक ही लक्ष्य होना चाहिए। वह है 'देश प्रथम'। जो बांटने का काम करते हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। पीआरडी जवानों का भत्ता 2019 तक 250 रुपए था। 2019 में इसे बढ़ाकर 375 किया। 2022 में 395 रुपए किया। फिर 500 किया।





योगी का ऐलान- पीआरडी जवानों का भत्ता 600 करेंगे

गोरखपुर में कैशलैस योजना शुरू की, 5 लाख तक इलाज फ्री होगा

शुभारंभ

तमसा संकेत, एजेंसी

गोरखपुर। सीएम योगी ने मंगलवार को गोरखपुर में पीआरडी (प्रांतीय रक्षक दल) जवानों के लिए 'मुख्यमंत्री पीआरडी परिवार कल्याण योजना' का शुभारंभ किया। इसमें पीआरडी जवान के परिवार का 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज होगा। सीएम ने पीआरडी जवानों के वर्दी भत्ते के 3000 रुपए उनके खातों में ट्रांसफर किए। इससे पहले लखनऊ में बनने वाले पीआरडी भवन का शिलान्यास किया। 1948 में गठित प्रांतीय रक्षक दल के जवान (स्वयंसेवक) पुलिस के काम में मदद करते हैं। योगी ने ऐलान किया कि जल्द ही पीआरडी जवानों का भत्ता रोजाना 600 किया जाएगा। इसकी तैयारी की जा चुकी है। अभी पीआरडी जवानों को 500 रुपए मिलते हैं। प्रदेश में 31 हजार पीआरडी जवान रजिस्टर्ड हैं। इसमें 2 हजार से ज्यादा महिलाएं हैं।

>> (शेष पेज 06 पर)



सीएम योगी ने कहा- अमेरिका-ईरान युद्ध में मिसाइले गिर रही थीं तो यहां नेता परेशान हो रहे थे

CM योगी ने कहा- अब दंगाई और माफिया हमेशा के लिए रसातल में चले गए हैं। आज यूपी बीमारू नहीं रहा। विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। हमने यहां की अर्थव्यवस्था को तीन गुना कर दिया है। पहले 43 हजार प्रति व्यक्ति आय थी, आज 1 लाख 20 हजार हो गई है। आज बजट 9 लाख 70 हजार करोड़ पहुंच गया है। वे लुटवाते थे, लूटते थे। प्रदेश का पैसा विदेशों में जमा करवाते थे। इन्होंने अपनी पीढ़ियों के लिए इतना पैसा जमा किया है। ये सोचते हैं कि कोई दिक्कत होगी तो वहां भाग जाएंगे। जिन्होंने दुबई में पैसा जमा किया है।

पैसा विदेशों में जमा करवाते थे, दिक्कत होने पर भागने का प्लान था

योगी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा- पिछली सरकारें अपनी पीढ़ियों के लिए पैसा जमा करती थीं। प्रदेश का पैसा विदेशों में जमा करवाते थे। ये सोचते हैं कि कोई दिक्कत होगी तो वहां भाग जाएंगे। अमेरिका-ईरान युद्ध में मिसाइल वहीं गिर रही थी, जहां पैसा जमा था। युद्ध वहां हो रहा था, परेशान नेता थे। अब दंगाई और माफिया हमेशा के लिए रसातल में चले गए हैं।

पिछली सरकारों ने माफिया के आगे घुटने टेक दिए थे

सीएम ने कहा- आरोप-प्रत्यारोप वही करते हैं जो कुछ कर नहीं पाते। उन्हें लगता है कि हम कर नहीं सके, इन्होंने कैसे कर दिया। यही उनकी समस्या है। वे माफिया के आगे घुटने टेक देते थे। यहां क्या नहीं था, सबकुछ था। उर्वरा भूमि, सबसे अच्छे प्रगतिशील किसान, पढ़ी-लिखी बेटी, अच्छे व्यापारी, प्रतिभाशाली युवा थे। जिन्होंने प्रदेश को बीमार बना दिया, वे यहां के लोगों का इलाज क्या कर पाते। पहले 43 हजार प्रति व्यक्ति आय थी, आज 1 लाख 20 हजार हो गई है।

सोनिया गांधी ने पीएम पद ठुकराने की वजह बताई

लिखा-दुख और अपनों को खोने की वजह से राजनीति में आईं

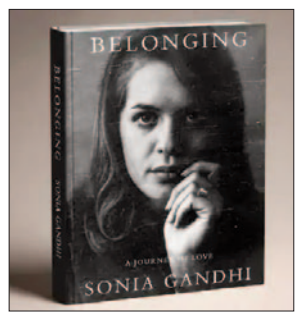
जिक्र

तमसा संकेत, एजेंसी

न्यूयॉर्क। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब 'Belonging: A Journey of Love' 10 नवंबर को प्रकाशित होगी। किताब में सोनिया ने इटली में बिताए बचपन से लेकर कैंब्रिज में राजीव गांधी से मुलाकात तक का जिक्र किया है। इस किताब में नेहरू-गांधी परिवार में शादी और परिवार में हुई हत्याओं के बाद बदली जिंदगी के बारे में लिखा है। इसमें राजनीति में उनके सफर और 2004 में प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं करने के फैसले से जुड़े अनुभव भी शामिल हैं। सोनिया का जन्म इटली के एक छोटे शहर में हुआ था। पढ़ाई के लिए इंग्लैंड के कैंब्रिज पहुंचने के दौरान उनकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई।

>> (शेष पेज 06 पर)

सोनिया ने कहा कि उनके परिवार के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन उनके इरादों, काम और मानवीय पहलुओं को उस तरह नहीं समझा गया। कई मायनों में यह किताब उनकी इंसानियत को समर्पित है।



पीएम केयर्स में घरेलू डोनेशन 30% घटा, ₹479 करोड़ रहा

नई दिल्ली। 2025 में पीएम केयर्स फंड में घरेलू दान 30% घटकर करीब 479 करोड़ रुपए रहा। विदेशी दान में भी कमी आई। यह 18% घटकर 92.8 लाख रुपए रह गया है। 2023 में घरेलू दान 681 करोड़ और विदेशी दान 1.13 करोड़ रुपए था। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 में फंड में टोटल रकम 7,173 करोड़ रुपए थी। 2025 में यह 8,452 करोड़ रुपए हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में कोविड महामारी फैलने के बाद पीएम केयर्स फंड बनाया था। इस फंड में फॉरेन फंडिंग 2020-21 में 495 करोड़ रुपए थी, जो अगले दो वित्त वर्षों में घटकर 40 करोड़ रुपए और 2.57 करोड़ रुपए रह गई। 2023-24 में विदेशी दान से 1.13 करोड़ रुपए मिले थे। 2024-25 में विदेशी योगदान 92.8 लाख रुपए रहा।

मौत के लिए जहरीले इंजेक्शन या गोली मारने जैसे तरीकों की मांग की गई थी

सुप्रीम कोर्ट में फांसी सिस्टम खत्म करने की याचिका खारिज

कार्यवाई

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मौत की सजा देने के लिए फांसी की मौजूदा व्यवस्था खत्म करने की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई आधार नहीं है, जिसके कारण फांसी को असंवैधानिक घोषित किया जाए। याचिका में फांसी को क्रूर, अमानवीय और दर्दनाम बताया गया था।

>> (शेष पेज 06 पर)



केंद्र ने फांसी को 'तेज और आसान' तरीका बताया था

2018 में केंद्र ने मौजूदा व्यवस्था का बचाव किया था।
गृह मंत्रालय ने हलफनामे में कहा था कि फांसी से मौत तेज और आसान होती है और इससे कैदी की पीड़ा अनावश्यक रूप से नहीं बढ़ती।



कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिका खारिज करने का मतलब यह नहीं है कि भविष्य में संवैधानिक समीक्षा का रास्ता बंद हो गया है। अगर ठोस वैज्ञानिक, मेडिकल या अनुभवजन्य सबूत सामने आते हैं, तो इस मुद्दे की दोबारा जांच की जा सकती है। कोर्ट ने कहा- केंद्र सरकार विशेषज्ञों की समिति बनाकर मौजूदा फांसी की व्यवस्था की व्यापक समीक्षा कर सकती है।

फास्ट न्यूज

देश में बनेंगे फाइटर जेट-टैंक और मिसाइल सिस्टम के उपकरण

नई दिल्ली। सरकार हथियारों-मिसाइलों और टैंक के ज्यादातर पार्ट्स भारत में ही बनाना चाहती है। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को 405 स्ट्रैटेजिक आइटम्स की छठी लिस्ट जारी की। इनमें अलग-अलग मशीनों के हिस्से, स्पेयर पार्ट्स, कंपोनेंट, सब-सिस्टम और रॉ मटेरियल शामिल है।

टीआरई-4 का नोटिफिकेशन जारी, 32,388 पदों पर निकली वैकेंसी

पटना। BPSC ने शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE-4) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। TRE-4 के तहत कुल 32,388 पदों पर भर्ती की जाएगी। 1 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। आवेदन की अंतिम तारीख 30 सितंबर है। फिलहाल परीक्षा की तारीख घोषित नहीं की गई है। TRE-4 और अन्य लंबित परीक्षाओं की मांग को लेकर छात्र कई दिनों से पटना के गर्दनीबाग में अनिश्चितकालीन 'छात्र न्याय सत्याग्रह' पर बैठे हैं। छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्र सत्याग्रह कर रहे हैं।

बीजेपी विधायक ने माता सीता को बताया 'मौत का सामान'

गुना। मध्य प्रदेश के गुना में मंगलवार को राज्य स्तरीय बलराम महोत्सव में बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य ने माता सीता को 'मौत का सामान' बताया। शाक्य ने रामायण, महाभारत और अन्य युद्धों का उदाहरण देते हुए कहा कि इन युद्धों में पुरुष मारे गए, एक भी महिला नहीं मरी।

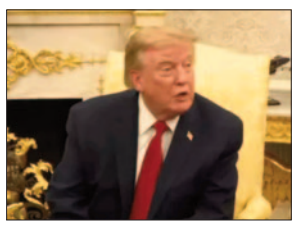
अमेरिका में भारत जैसा चुनावी सिस्टम हो : ट्रम्प

हर भारतीय वोटर के पास फोटो आईडी, अमेरिका में बिना इसके इलेक्शन क्यों

अपील

तमसा संकेत, एजेंसी

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मंगलवार को भारत की चुनाव व्यवस्था का हवाला देते हुए 'सेव अमेरिका एक्ट' को पास कराने की अपील की है। ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट में लिखा- इस महीने की शुरुआत में, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हमारे प्रशासन से पूछा था कि अमेरिका में वैध फोटो ID के बिना चुनाव कैसे हो सकते हैं? ट्रम्प ने आगे कहा- हमें अब सेव अमेरिका एक्ट पास करना होगा। ट्रम्प ने अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया को और



सख्त बनाने पर जोर दिया। उनका कहना है कि इससे अमेरिकी चुनावों की सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ेगी। सेव अमेरिका एक्ट अमेरिका में मतदाता पंजीकरण और मतदान से जुड़े नियमों को और सख्त करने वाला एक विधेयक प्रस्ताव है। इसके तहत वोटर रजिस्ट्रेशन के समय नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण और मतदान के समय फोटो ID दिखाना जरूरी होगा।

>> (शेष पेज 06 पर)

पहले बागी विधायकों की अयोग्यता पर फैसला हो : उद्धव

सुप्रीम कोर्ट में अपील- असली शिवसेना और पार्टी सिंबल किसका, यह बाद में देखें

आरोप

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। उद्धव ठाकरे गुट ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि असली शिवसेना किसकी, इसका फैसला विधायकों की अयोग्यता से जुड़े के बाद होना चाहिए। उद्धव गुट का कहना है कि पहले यह तय हो कि बागी विधायक अयोग्य हैं या नहीं, इसके बाद चुनाव आयोग यह तय करे कि असली राजनीतिक पार्टी कौन-सा गुट है। यह दलील एडवोके कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच के सामने दी। बेंच उद्धव गुट की याचिकाओं पर छठे दिन दलीलें सुन रही थी। जिनमें चुनाव आयोग के एकनाथ शिंदे गुट



को असली शिवसेना मानने और पार्टी का नाम और धनुष-बाण निशान देने के फैसले को चुनौती दी गई है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष ने विधानसभा में बहुमत को एकमात्र आधार बनाकर शिवसेना के संगठनात्मक पक्ष को नजरअंदाज किया। 13 अगस्त को भी उद्धव गुट ने कहा था कि संविधान के प्रावधानों की ऐसी व्याख्या नहीं की जा सकती, जिससे उस "गलती" को बढ़ावा मिले जिसे रोकने के लिए दलबदल विरोधी कानून बनाया गया है।

>> (शेष पेज 06 पर)

सिब्बल ने कहा, "यह माना गया है कि उद्धव पक्षप्रमुख हैं। उन्होंने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। अब अध्यक्ष यह कैसे कह सकते हैं कि उन्हें मान्यता देने की जरूरत नहीं है?" सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के सुभाष देसाई मामले के फैसले का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि विधायी दल में बंटवारे का मतलब अपने आप राजनीतिक दल में बंटवारा नहीं होता।

39 विधायकों को अयोग्यता के नोटिस

सिब्बल ने कहा कि अयोग्यता का सामना कर रहे बागी विधायकों की संख्या पहले 16 थी। बाद में यह 22 और आखिर में 39 हो गई। इन विधायकों पर अलग-अलग उल्लंघनों के आरोप थे। इनमें विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव और उसके बाद हुए विश्वास प्रस्ताव के दौरान पार्टी व्हिप का पालन नहीं करना भी शामिल था।

10 जनवरी 2024 के फैसले पर सवाल

सिब्बल ने विधानसभा अध्यक्ष के 10 जनवरी 2024 के फैसले पर सवाल उठाया। अध्यक्ष ने अयोग्यता याचिकाएं खारिज कर दी थीं और विधानसभा में बहुमत के आधार पर शिंदे गुट को असली शिवसेना माना था। सिब्बल ने कहा कि अध्यक्ष ने शिवसेना के 2018 के नेतृत्व ढांचे को नजरअंदाज करके अपने अधिकार से बाहर जाकर फैसला किया। अध्यक्ष ने कहा था कि 2018 का पार्टी संविधान शिवसेना के वास्तविक ढांचे के अनुरूप नहीं था। सिब्बल ने इस दावे को संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत कानूनी आधार के बिना बताया।

विधायकों की अयोग्यता पर फैसला पहले लेने की अपील

सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग और महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने कानून को गलत तरीके से समझा। उन्होंने विधायकों की संख्या में बहुमत को ही राजनीतिक पार्टी मान लिया, जबकि दोनों अलग चीजें हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को यह तय करना चाहिए कि असली पार्टी कौन-सी है, लेकिन यह फैसला बागी विधायकों के खिलाफ चल रही अयोग्यता की कार्यवाही पूरी होने के बाद ही होना चाहिए। सिब्बल ने कहा, "अगर इन विधायकों को आखिर में अयोग्य ठहराया जाता है, तो विधानसभा में उनकी संख्या को नहीं गिना जाना चाहिए।"

प्रदर्शन : सुप्रीम कोर्ट में कहा- हिस्ट्रीशीटर शामिल हुए, बैरिकेड तोड़े, लेकिन हमने ज्यादा बल प्रयोग नहीं किया

सीजेपी का संसद मार्च गैरकानूनी था : दिल्ली पुलिस

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 20 जुलाई का संसद मार्च गैरकानूनी था। इसकी परमिशन नहीं थी। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में कई हिस्ट्रीशीटर भी आ गए थे। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सचिन शर्मा ने हलफनामा दाखिल कर ये जानकारी दी। इसे पुलिस ज्यादती की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिकाओं के जवाब के तौर पर पेश किया गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हाई लेवल कमेटी बनाएगा। फेशियल रिकग्निशन के इस्तेमाल पर- फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर से हर व्यक्ति की प्रोफाइल दर्ज नहीं होती और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों

"पुलिस ने बताया कि संसद मार्च में प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े और पुलिस से मारपीट की, जिससे प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं रहा। हालात संभालने के लिए बल प्रयोग किया गया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग नहीं किया गया।



की निगरानी नहीं की जाती। इसका इस्तेमाल गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड वालों की पहचान के लिए होता है। सिर्फ फेशियल रिकग्निशन के आधार पर कार्रवाई नहीं होती। फील्ड वेरिफिकेशन भी किया जाता है। छोटे मामलों या ट्रैफिक चालान वालों की पहचान नहीं की जाती।

पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, जबकि CJP ने पुलिस पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल का आरोप लगाया। पुलिस कार्रवाई में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के घायल होने की रिपोर्ट सामने आई।

हाईलेवल कमेटी करेगी जांच

सुप्रीम कोर्ट ने CJP के नेतृत्व वाले छात्र प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई के आरोपों की जांच के लिए हाईलेवल कमेटी बनाने का फैसला किया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, पूर्व DGP, पूर्व CBI प्रमुख समेत अन्य सदस्य होंगे। कोर्ट बुधवार को कमेटी के गठन का औपचारिक आदेश जारी करेगा। इससे पहले याचिकाकर्ताओं और अन्य पक्षों से सदस्यों के नाम पर सुझाव लिए जाएंगे।

सीजेपी प्रोटेस्ट 49 दिन चला, 20 जुलाई की पुलिस कार्रवाई के बाद बढ़ा विवाद

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का जंतर-मंतर प्रदर्शन 20 जून से शुरू हुआ था। 20 जुलाई के 'संसद चलो' के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, जबकि CJP ने पुलिस पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल का आरोप लगाया। पुलिस कार्रवाई में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के घायल होने की रिपोर्ट सामने आई।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी रिपोर्ट में चंपत-मिश्रा के नाम नहीं

बाकी 8 आरोपी पहले ही जेल में, एसआईटी ने फाइनल जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी

जांच

तमसा संकेत, एजेंसी

अयोध्या। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच के लिए यूपी सरकार की बनाई SIT ने सोमवार रात फाइनल रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक, इसमें ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा का नाम नहीं है। बाकी 8 आरोपी पहले ही जेल में हैं। यूपी के गृह विभाग ने रिपोर्ट राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास को सौंपी है। इसे राम मंदिर ट्रस्ट की 2 सितंबर को होने वाली बैठक में रखा जाएगा। ट्रस्ट ने ही उत्तर प्रदेश सरकार से चढ़ावा चोरी की SIT जांच का अनुरोध किया था। यूपी सरकार ने 13 जून को लखनऊ



मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की SIT बनाई थी। आईजी रेंज किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन कुमार इसके सदस्य थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने SIT जांच की कमान IPS को सौंपने और फाइनेंस एक्सपर्ट को शामिल करने के निर्देश दिए थे। 20 जुलाई को नई SIT बनी, जिसमें लखनऊ रेंज के IG किरण एस, डीआईजी अयोध्या सोमेन वर्मा और अयोध्या एसएसपी गौरव ग्रोवर को शामिल किया गया।

जिन बच्चों को क्लास में होना चाहिए, वे सड़कों पर उतरने को मजबूर, यही है भाजपा सरकार का असली चेहराः अनित रावत

प्रदेश में शिक्षकों के 77,400 से अधिक पद खाली

प्रदर्शन

- गरीब, मजदूर और किसान के बच्चों को अशिक्षित रखकर अपनी तानाशाही और गुंडागर्दी चलाना चाहती है सरकारः अनित रावत
- 77,400 रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती कर सरकारी स्कूलों की दुर्दशा सुधारे सरकार, वरना होगा बड़ा आंदोलनः अनित रावत



तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में सरकारी विद्यालयों की जर्जर स्थिति, बुनियादी सुविधाओं के अभाव और शिक्षकों के 77,400 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी की छात्र विंग ASAP (Association of Students for Alternative Politics) ने मंगलवार को राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे के निकट जीपीओ पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। छात्रविंग के प्रदेश अध्यक्ष अनित रावत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग उठाई। इस दौरान अनित रावत ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूल आज बदहाली के आंसू रो रहे हैं और सरकार युवाओं व बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस के भाषण पर कड़ा प्रहार करते हुए अनित रावत ने कहा कि जब देश का युवा और बच्चे बेहतर शिक्षा व रोजगार के लिए सवाल पूछते हैं, तो प्रधानमंत्री उन्हें 'नक्सली दिमाग' कहते हैं। रावत ने दो टूक कहा कि अगर शिक्षा के लिए हिसाब मांगना और रोजगार के लिए सवाल पूछना आपकी नजर में नक्सलवाद है, तो हमें यह स्वीकार है। प्रधानमंत्री को यह समझना चाहिए कि युवा अपना हक मांग रहा है, कोई खैरात नहीं। अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए छात्रों पर ऐसा लांछन लगाना शर्मनाक है। अनित रावत ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है—वे चाहते हैं कि गरीब, मजदूर और किसान का बच्चा अशिक्षित रहे। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी जानते हैं कि जिस दिन गरीब का बच्चा पढ़-लिख जाएगा, वह उनकी तानाशाही और गुंडागर्दी के खिलाफ सवाल खड़ा करेगा। इसी डर से सरकारी स्कूलों को बर्बाद किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की छात्रविंग मांग करती है कि जल्द से जल्द सभी 77,400 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएं ताकि हर गरीब बच्चे को बेहतर शिक्षा मिल सके। इस दौरान छात्रविंग के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अंशुल यादव, प्रदेश संगठन मंत्री आशीष , निलेश, चन्द्रजीत, शाहिद सहीत सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने एक स्वर में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार और नई शिक्षक भर्ती की मांग की।

नौजवानों को नौकरी देने के बजाय बेरोजगार रखना चाहती है सरकारः अनित रावत

स्कूलों में न कमरे हैं न शिक्षक, बदहाल व्यवस्था के खिलाफ सड़क पर उतरे मासूम बच्चेः अनित रावत

प्रदर्शन को संबोधित करते हुए छात्रविंग के प्रदेश अध्यक्ष अनित रावत ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में सरकारी विद्यालयों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। विद्यालयों में बैठने के लिए कमरे नहीं हैं और जहाँ कमरे हैं, वहाँ शिक्षक नदारद हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि छोटे-छोटे बच्चे अपनी पढ़ाई और शिक्षकों की मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। जिन बच्चों को आज क्लास में बैठकर अपना भविष्य संवारना चाहिए था, वे आज रोड जाम कर सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि 'हमें टीचर दे दो'।



77,400 शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती न करना सरकार की मंशा पर उठाता है सवालः अनित रावत

अनित रावत ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में लगभग 77,400 से अधिक शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। यदि सरकार इन पदों पर तत्काल नौजवानों की नियुक्ति कर दे, तो स्कूलों में शिक्षकों की कमी भी पूरी हो जाएगी और हजारों युवाओं को रोजगार भी मिल जाएगा। लेकिन केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार जानबूझकर युवाओं को बेरोजगार रखना चाहती है। सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा और रोजगार कभी रहा ही नहीं है।

फास्ट न्यूज

बारिश में पिकप भवन पहुंचे अभ्यर्थी

लखनऊ । लखनऊ में UPSSSC की जूनियर असिस्टेंट भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का गुस्सा सड़क पर दिखा। 5512 पदों की भर्ती का अंतिम परिणाम 4 साल बाद भी जारी नहीं हुआ है। इसे लेकर मंगलवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी गोमतीनगर स्थित पिकप भवन पहुंचे। तेज बारिश के बावजूद अभ्यर्थी प्रदर्शन करते रहे। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई।

शहीद पथ पर डीआइजी की कार में पीछे से टक्कर

लखनऊ । लखनऊ के शहीद पथ पर मंगलवार दोपहर DIG हेमराज मीणा की कार हादसे का शिकार हो गई। हुसड़िया चौराहे के पास पीछे से आ रही कार ने उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी। इसके बाद DIG की कार आगे चल रही गाड़ी से जा भिड़ी। हादसे में हेमराज मीणा पूरी तरह सुरक्षित हैं, जबकि उनकी कार का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर जांच शुरू कर दी। हादसे के बाद मौके पर कुछ देर अफरा-तफरी का माहौल रहा। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई।

लखनऊ से यूपी के शहरों में पहुंचेगी 'जेनजी महाजुटान यात्रा'

लखनऊ। लखनऊ यूपी प्रेस क्लब में आइसा ने 'GenZ Rising' अभियान के उत्तर प्रदेश चैप्टर के तहत GEN-Z महाजुटान यात्रा की घोषणा की। यह यात्रा जंतर-मंतर आंदोलन से जुड़े नेताओं के नेतृत्व में प्रदेश के अलग-अलग शहरों में पहुंचेगी। यात्रा का उद्देश्य छात्रों और युवाओं के स्थानीय मुद्दों को प्रदेशव्यापी आंदोलन से जोड़ना है। यात्रा में मुख्य रूप से नेहा और मनीष शामिल रहेंगे।

मयूर रेसिडेंसी विस्तार में महिलाओं ने धूमधाम से मनाया हरियाली तीज उत्सव



तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। मयूर रेसिडेंसी विस्तार महिला ग्रुप की ओर से हरियाली तीज के पावन पर्व पर भव्य एवं रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सावन की हरियाली और उल्लास से सराबोर इस कार्यक्रम में कॉलोनी की महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना से हुआ। इसके बाद श्रद्धा उपाध्याय ने मधुर कजरी गीत प्रस्तुत कर कार्यक्रम में सावन की रंगत भर दी। मंच संचालन नीतू शर्मा एवं अपर्णा सिंह ने संयुक्त रूप से किया, जबकि अर्चना सिंह ने भी संचालन में सहयोग दिया। विभिन्न खेलों एवं मनोरंजक गतिविधियों को आकर्षक बनाने में पल्लवी और जया श्रीवास्तव का विशेष योगदान रहा।

सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान स्नेहा, कीर्ति सिंह, अनीता पटेल, भावना, पूजा, कीर्ति गुप्ता, नेहा, मीनू, श्वेता, गिरीश और नीलम ने लोकगीतों एवं बॉलीवुड गीतों पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। महिलाओं ने विभिन्न खेलों और मनोरंजक गतिविधियों में भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की संयोजिका आभा श्रीवास्तव ने सभी प्रतिभागियों एवं सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन महिलाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मंच देने के साथ-साथ आपसी सौहार्द, भाईचारे और भारतीय संस्कृति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

पीएसी तैनात कर 200 भैंसें उठवाईं

लोगों ने टीम पर हमला किया था, मेयर बोलीं- पूरा इलाका साफ कर देंगे

तमसा संकेत, एजेंसी

दुबग्गा (लखनऊ)। लखनऊ के पारा में नगर निगम की कैटल कैचर टीम पर हमले के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। मंगलवार को नगर निगम की टीम के साथ 3 थानों की फोर्स और एक कंपनी पीएसी बल पहुंचा। सभी जवान हेलमेट, बुलेटप्रूफ जैकेट पहने हुए थे। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में निगम की टीम ने 4 मोहल्लों से करीब 200 भैंसें उठवा लीं।

टीमों के बाद मेयर सुषमा खर्कवाल और नगर आयुक्त गौरव कुमार भी पहुंचे। यहां मेयर ने कहा- जो पुलिस आपकी सुरक्षा करती है, उस पर हमला स्वीकार नहीं है। पूरा इलाका साफ कर देंगे। इन लोगों ने पुलिस और नगर निगम की टीम पर हमला किया। आज पूरे इलाके से भैंसें उठवा ली गई हैं। दरोगा पर हमला कर सिर फोड़ दिया गया था।

दरअसल, रविवार को टीम एक दरोगा और कुछ पुलिसबल के साथ





पहुंची थी तो अवैध डेयरी संचालकों ने उन पर हमला कर दिया था। पुलिस ने पशु कल्याण अधिकारी अवधेश कुमार की शिकायत पर अबरार, इमरान, सालून, सुबिल, सराफत, अतीक, आशिफ, वारिश, नसीम, रानू, जीशान, नाफिश समेत 24 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कई को हिरासत में लिया था। सोमवार को दो महिलाओं को भी गिरफ्तार किया था।

इस अभियान में नगर निगम की कैटल कैचर टीम के साथ पारा, दुबग्गा और काकोरी थाने की फोर्स मौजूद है। मौके पर एसीपी काकोरी शकील अहमद सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे।

इंस्पेक्टर को मारा, उसका सख्त जवाब दिया जाएगा

मेयर सुषमा खर्कवाल ने कहा- यह पुलिस और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई है। इन्होंने जिस तरह से नगर निगम के कर्मचारियों और इंस्पेक्टर को मारा, वह बहुत ही गलत काम किया था। इस पर सख्त कार्रवाई होगी। इलाका पूरा साफ कर देंगे। आज ये इलाका पूरा साफ कर दिया है। इन हमलावरों को आज जवाब दिया जा रहा है। पुलिस आपकी सुरक्षा करने के लिए है, न कि आपसे मार खाने के लिए।

तिकोनिया, गायत्री विहार, ज्ञानेंद्र विहार में कार्रवाई

तिकोनिया, गायत्री विहार, ज्ञानेंद्र विहार में नगर निगम की टीम और पुलिस फोर्स ने सबसे पहले कार्रवाई की। यहां के करीब 10 घरों और डेयरियों से भैंसों को बाहर निकाला। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की वजह से लोगों ने पिछली बार की तरह विरोध करने की हिम्मत नहीं दिखाई। इन मोहल्लों में कार्रवाई के बाद टीम हैदर कैनाल के पास कुल्हरकट्टा रोड की तरफ गई। वहां पर डिप्टी खेड़ा में भैंसों को पकड़ा जा रहा है। महिलाओं ने टीम के कर्मचारियों को गाली दी लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी के चलते विरोध चल नहीं सका।

सीएम योगी के निर्देश पर आयुष्मान योजना में गड़बड़ी करने वाले अस्पतालों पर कसा शिकंजा

आयुष्मान मरीजों के इलाज में लापरवाही पर सरकार सख्त

तमसा संकेत, संवाददाता



लखनऊ। योगी सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों के इलाज में लापरवाही, नियमों के उल्लंघन और वित्तीय अनियमितताओं पर लगातार आयुष्मान योजना से जुड़े अस्पतालों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वर्ष 2020 से 2026 तक कुल 866 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनमें सबसे अधिक 648 अस्पतालों का डी-इम्पैनलमेंट किया गया जबकि 61 अस्पतालों को योजना से निलंबित किया गया। वहीं 17 अस्पतालों में विशेषता को डी-इम्पैनलमेंट किया गया है। इसके अलावा 140 अस्पतालों पर पेनाल्टी की कार्रवाई करते हुए साढ़े आठ करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। इनसे अब तक 4 करोड़ रुपये से अधिक जुर्माने की धनराशि वसूली गई है। साचीज की सीईओ अर्चना वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों के गुणवत्तापूर्ण इलाज को लेकर काफी गंभीर हैं। ऐसे में सीएम योगी की मंशा के अनुरूप मरीजों के इलाज में लापरवाही और मानकों को पूरा न करने वाले अस्पतालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाती है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 में लापरवाही पर 318 अस्पतालों के खिलाफ एक्शन लिया गया। इनमें 242 अस्पतालों को भारत सरकार के 35 इंडीकेटस पूरा न करने पर डी-इम्पैनलमेंट किया गया जबकि 61 अस्पतालों को निलंबित किया गया। इनमें 15 अस्पतालों की स्पेशियलिटी का डी-इम्पैनलमेंट भी शामिल है।



866 अस्पतालों पर कार्रवाई

61 अस्पतालों को किया गया निलंबित, 648 अस्पतालों को किया गया डी-इम्पैनलमेंट

दो वित्तीय वर्षों में 140 अस्पतालों पर लगाई गई 8.53 करोड़ रुपये की पेनाल्टी

इससे पहले वर्ष 2025 में 16 अस्पतालों पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें 14 अस्पतालों का डी-इम्पैनलमेंट, दो अस्पतालों की स्पेशियलिटी का डी-इम्पैनलमेंट किया गया।

पिछले दो वर्षों में 140 अस्पतालों पर लगाई गई पेनाल्टी

साचीज की सीईओ ने बताया कि वर्ष 2024 में 27 अस्पतालों पर कार्रवाई हुई। वहीं वर्ष 2023 में 203, वर्ष 2022 में 41, वर्ष 2021 में 44 और वर्ष 2020 में 77 अस्पतालों पर कार्रवाई की गई। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 60 अस्पतालों के खिलाफ 3,45,66,861 रुपये पेनाल्टी लगाई गई। इनमें अस्पतालों से अब तक 3,19,27,958 रुपये की वसूली हो चुकी है जबकि शेष धनराशि की वसूली की कार्रवाई चल रह है।

चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से में उतरकर भारत ने रचा इतिहास

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। चंद्रयान-3 के लैंडर की चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से में सफल लैंडिंग भारत की वैज्ञानिक क्षमता का बड़ा प्रमाण है। जिस उपलब्धि को कभी लगभग असंभव माना जाता था, भारत ने उसे संभव कर दिखाया। यह बात इस्ट्रैक, बंगलूरू के निदेशक एमआर राघवेन्द्र ने मंगलवार को सीएमएस गोमतीनगर कैंपस में आयोजित राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस-2026 के कार्यक्रम में कही।

उन्होंने कहा कि चंद्रयान-3 की सफलता सिर्फ देश की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमता को नहीं दर्शाती, बल्कि यह युवाओं को विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करती है। ऐसे में इस उपलब्धि को कमतर नहीं आंका जा सकता।

कार्यक्रम में विद्यार्थियों को भारत के प्रमुख अंतरिक्ष अभियानों और उपलब्धियों की जानकारी दी गई। चंद्रयान-3, आदित्य-L1 और SPADEX जैसे महत्वपूर्ण अभियानों पर विशेष वार्ता हुई। विद्यार्थियों ने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों से संवाद कर अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान से जुड़े सवाल पूछे।

कार्यक्रम में अंतरिक्ष अभियानों से जुड़े विभिन्न मॉडलों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इसके जरिए विद्यार्थियों को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, अंतरिक्ष तकनीक और वैज्ञानिक उपलब्धियों को करीब से समझने का अवसर मिला।



- इसरो वैज्ञानिक बोले- जिसे दुनिया ने असंभव माना, भारत ने कर दिखाया

वारदात : 3 गोलियां मारीं, पत्नी को मायके ले जाने से नाराज था, भीड़ ने बांधकर पीटा

रिटायर्ड फौजी ने बुलेटप्रूफ जैकेट पहनकर साले की हत्या की

तमसा संकेत, एजेंसी



प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में रिटायर्ड फौजी ने सगे साले की हत्या कर दी। वह सुल्तानपुर से साले की मेडिकल स्टोर की दुकान पहुंचा। वहां ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जब तक साला कुछ समझ पाता, तब तक तीन गोलियां उसे लग गईं। वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। आरोपी बुलेटप्रूफ जैकेट पहनकर पहुंचा था।

फौजी ने मौके से भागने की कोशिश की। भीड़ ने उसे पकड़ लिया। रस्सी से बांधकर पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह आरोपी फौजी कपिल यादव (43) को भीड़ से बचाया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया। आसपास के लोग साले देवेंद्र यादव (48) को जिला अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फौजी कपिल यादव का पत्नी प्रियंका से विवाद चल रहा था। सोमवार को देवेंद्र अपने जीजा के घर सुल्तानपुर गया। वहां से बहन प्रियंका और बच्चों को साथ ले आया था। इसी बात से कपिल साले से नाराज था। वारदात मंगलवार दोपहर 12 बजे जिला मुख्यालय से 25 किमी दूर कोहंडौर थाना क्षेत्र की है।



15 साल पहले हुई थी शादी, 6 महीने से पत्नी से था विवाद

फौजी कपिल (43) की 15 साल पहले प्रियंका से शादी हुई थी। पिछले साल कपिल फौज से रिटायर हो गया था। वह सुल्तानपुर के जिला अस्पताल में गार्ड की नौकरी करने लगा था। 6 महीने से पति-पत्नी में विवाद चल रहा था। सोमवार को फिर किसी बात पर कपिल का प्रियंका से विवाद हो गया। प्रियंका ने अपने भाई देवेंद्र को फोन कर दिया। देवेंद्र सुल्तानपुर प्रियंका के घर पहुंचा। वहां प्रियंका और उसके बच्चे को लेकर घर आ गया।

प्रतापगढ़ में मदाफरपुर बाजार में देवेंद्र की मेडिकल स्टोर की दुकान है। सोमवार को वह दुकान पर बैठा था। तभी कपिल सुल्तानपुर से वहां पहुंच गया। वह फौजी की वर्दी में था। दोनों के बीच बहस हुई। कपिल ने धमकाया कि तुम प्रियंका को लेकर कैसे आ गए। इसी दौरान बात बढ़ी तो कपिल ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी।

आईटीआई और पॉलिटेक्निक में रिक्त पदों पर होगी अनुदेशकों की नियुक्ति

तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार कटिबद्ध

- राजकीय गोविंद बल्लभ पंत पॉलिटेक्निक, लखनऊ सहित विभिन्न जिलों में रिक्त पदों को भरने के दिए गए निर्देश
- भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने तक रखे जा रहे हैं अनुदेशक



तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। प्रदेश में युवाओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से समाज कल्याण विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। समाज कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत संचालित राजकीय आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों में अनुदेशकों (Instructors) के रिक्त पदों पर जल्द ही पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने तक रिटायर्ड शिक्षकों आदि को अनुदेशक के रूम में लगाया जा रहा है।

40 पद हैं खाली

वर्तमान में राजकीय गोविंद बल्लभ पंत पॉलिटेक्निक, मोहन रोड, लखनऊ में 07 पद, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI), बख्शी का तालाब, लखनऊ में 23 पद, राजकीय आईटीआई/पॉलिटेक्निक, गोरखपुर में 09 पद और राजकीय आईटीआई/पॉलिटेक्निक, प्रतापगढ़ में 01 पद रिक्त है।

बयान

हमारी सरकार युवाओं के कौशल विकास और उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

अनुदेशकों की नियुक्ति होने से संस्थानों में शैक्षणिक स्तर मजबूत होगा और छात्रों को आधुनिक तकनीकों का बेहतर व्यावहारिक ज्ञान मिल सकेगा। पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया के जरिए योग्य अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है।

असीम अरुण

11 हजार वोल्ट लाइन से झुलसा गौरव

हाथ-पैर गंवाए, सपा जिलाध्यक्ष ने दी 50 हजार की मदद

हादसा

समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेश कुमार यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की।

तमसा संकेत, एजेंसी

उन्नाव। उन्नाव में 11 हजार वोल्ट की बिजली लाइन की चपेट में आने से 12 वर्षीय गौरव गंभीर रूप से झुलस गया। इस हादसे में गौरव का एक हाथ और एक पैर का पंजा काटना पड़ा है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और इलाज जारी है। भगवंतनगर विधानसभा क्षेत्र के टिकरी बैरागर गांव में पीड़ित परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेश कुमार यादव मंगलवार को



गौरव के घर पहुंचे। उन्होंने बच्चे का हाल जाना और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर परिवार को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता का चेक दिया। टिकरी बैरागर गांव निवासी हरी निषाद का पुत्र गौरव निषाद कुछ दिन पहले जामुन तोड़ने के लिए एक पेड़ पर चढ़ा था। परिजनों ने बताया कि पेड़ के बीच से 11 हजार वोल्ट की बिजली लाइन गुजर रही थी, जिसे गौरव देख नहीं पाया। बिजली के तार के संपर्क में आते ही वह करंट की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गया। हादसे में गौरव का एक हाथ और एक पैर का पंजा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया

66 सपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को इलाज के लिए जमीन बेचने की नौबत आना बेहद चिंताजनक है। ऐसे समय में सरकार और प्रशासन को पीड़ित परिवार की मदद के लिए आगे आना चाहिए। इस दौरान सपा युवजन सभा के प्रदेश मंत्री नितिन पटेल, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष राधे लाल निषाद, जिला उपाध्यक्ष शिवशंकर गौतम, सैय्यद इरफान, सपा युवजन सभा जिलाध्यक्ष अमन अंजुम, रमेश यादव, मुलायम हरिशंकर पटेल, रामविलास यादव, मुन्ना गुप्ता, विशम्भर यादव और ब्लॉक अध्यक्ष विजय यादव सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

था। डॉक्टरों को इलाज के दौरान उसके दोनों अंगों के इन हिस्सों को काटना पड़ा। गौरव की हालत अभी भी गंभीर है। परिवार



की आर्थिक स्थिति कमजोर है और बेटे के इलाज का खर्च जुटाने के लिए उन्हें अपनी जमीन तक बेचनी पड़ रही है। सपा जिलाध्यक्ष राजेश कुमार यादव ने परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। राजेश कुमार यादव ने इस हादसे के लिए बिजली विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया और विभाग की कड़ी निंदा की। उन्होंने डीएम से मांग की है कि मामले की गहन जांच कर दोषी बिजली कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने पीड़ित परिवार को बच्चे के इलाज के लिए पांच लाख रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराने की भी मांग की। यादव ने क्षेत्रीय विधायक और सांसद से भी अपनी-अपनी निधि से परिवार को पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की अपील की।

चोरों का तांडव, एक ही रात तीन घरों को बनाया निशाना

तमसा संकेत, एजेंसी

सूरतगंज (बाराबंकी)। मोहम्मद-पुर खाला थाना क्षेत्र में सोमवार की देर रात एक गांव में अज्ञात चोरों ने जमकर तांडव मचाया। चोरों ने एक के बाद एक घर को निशाना बनाते रहे , जिसमें एक घर से एक ऑटो रिक्शा की दो बैटरियां, गैस सिलेंडर, पीतल का तसला, दूसरे घर से मोबाइल फोन और सूटकेस सहित अन्य सामान चोरी कर लिया गया। वहीं तीसरे घर में पक्की दीवार में सेंध लगाकर चोरी का प्रयास किया गया, लेकिन घर के अंदर सामान रखे होने के कारण चोर प्रवेश नहीं कर सके और उनका प्रयास असफल हो गया। एक ही रात में तीन घरों को निशाना बनाए जाने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि सोमवार की देर रात गांव के अधिकांश लोग अपने-अपने घरों में सो रहे थे। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने



मसुरिहा ग्राम पंचायत के रानीपुरवा गांव निवासी सलीम पुत्र इसहाक के घर को निशाना बनाया। चोरों ने घर के बाहर खड़े ऑटो रिक्शा से दो बैटरियां निकाल लीं। इसके बाद घर के अंदर रखा एक गैस सिलेंडर और एक फूल का तसला भी चोर उठा ले गए। चोरों ने बड़ी सफाई से वारदात को अंजाम दिया और किसी को भनक तक नहीं लगी। इसके बाद चोरों ने इसी गांव के रामकुमार पुत्र कालीदीन के घर को निशाना बनाया। यहां से चोर एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन और एक सूटकेस चोरी कर ले गए। लगातार दो घरों में चोरी करने के बाद चोरों ने गांव के ही राजकुमार के घर में भी घुसने का प्रयास किया। राजकुमार के घर में प्रवेश करने के लिए चोरों ने पक्की दीवार में सेंध लगा दी। हालांकि जिस स्थान पर सेंध लगाई गई थी, वहां जंगाल और बाल्टी रखी होने के कारण चोर अंदर प्रवेश नहीं कर सके। काफी प्रयास के बाद भी घर में प्रवेश न कर पाने पर चोरों को खाली हाथ लौटना पड़ा। इस तरह राजकुमार के घर में चोरी की वारदात होने से बाल-बाल बच गई। घटना की जानकारी परिवारी-जनों को करीब रात डेढ़ बजे हुई। एक ही रात में गांव के तीन घरों को चोरों द्वारा निशाना बनाए जाने की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। पीड़ित परिवारों ने तत्काल मामले की सूचना डायल 112 पीआरवी पुलिस और सूरतगंज चौकी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया।

फास्ट न्यूज

उन्नाव मार्ग पर ऑटो-बाइक की हुई भिड़ंत

उन्नाव। उन्नाव-संडीला मार्ग पर मंगलवार दोपहर एक सड़क हादसे में ऑटो सवार एक युवक की मौत हो गई। अजमतनगर गांव के पास तेज रफ्तार बाइक और ऑटो रिक्शा की भिड़ंत में यह दुर्घटना हुई। हादसे में बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि ऑटो चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। मृतक की पहचान औरास थाना क्षेत्र के रायपुर राई गांव निवासी शिव प्रसाद (42) पुत्र जानकी के रूप में हुई है।

हरदोई में पेंट चोरी का खुलासा

हरदोई। हरदोई के सुरसा थानाक्षेत्र में पुलिस ने पेंट चोरी के एक मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने इस संबंध में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से चोरी किया गया पूरा माल और घटना में प्रयुक्त दो कारें भी बरामद की गई हैं। पुलिस के अनुसार, 3 अगस्त को बदायूं जिले के उसहैत थाना क्षेत्र के ककोरी निवासी सुधीर पुत्र धनपाल ने सुरसा थाने में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि लखनऊ-हरदोई मार्ग पर बल्लीपुर टोल प्लाजा के पास उनकी डाला गाड़ी से अज्ञात लोगों ने पेंट के डिब्बे चोरी कर लिए थे।

परिषदीय स्कूलों में तैयार हुईं 200 राखियां

उन्नाव। उन्नाव के नवाबगंज विकासखंड के परिषदीय विद्यालयों के बच्चों ने सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए लगभग 200 राखियां तैयार की हैं। मंगलवार दोपहर खंड शिक्षा अधिकारी शुचि गुप्ता के नेतृत्व में बच्चों और शिक्षकों के एक दल ने इन राखियों को जिलाधिकारी को सौंपा। इन राखियों को रक्षाबंधन के अवसर पर जिलाधिकारी के माध्यम से सेना के जवानों तक पहुंचाया जाएगा।

बारिश से झोपड़ी की कच्ची दीवार ढही

पति की मौत, पत्नी और 18 माह की मासूम गंभीर रूप से घायल

तमसा संकेत, एजेंसी

हरदोई। हरदोई में लगातार बारिश के बीच सोमवार देर रात कच्ची दीवार ढहने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसा देहात कोतवाली क्षेत्र के बंदरहिया बंजारन पुरवा में रात करीब 12:30 बजे हुआ। मलबे में दबने से व्यक्ति की पत्नी और 18 माह की बेटी गंभीर रूप से घायल हो गईं। ग्रामीणों ने तीनों को मलबे से बाहर निकालकर मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने पति को मृत घोषित कर दिया। मंगलवार दोपहर 2:45 बजे शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मृतक की पहचान 35 वर्षीय महबूब के रूप में हुई है। वह चूड़ी की फेरी लगाकर परिवार का पालन-पोषण करते थे। महबूब



पत्नी और बच्चों के साथ कच्ची दीवारों वाली झोपड़ी में रहते थे। पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण झोपड़ी की दीवारें कमजोर हो गई थीं। हादसे से कुछ देर पहले महबूब के दो बड़े बच्चे 5 वर्षीय रजा हुसैन और 3 वर्षीय खैरुन्निसा टॉयलेट के लिए बाहर गए थे। उनकी 33 वर्षीय मां नफीसा दोनों बच्चों को बाहर छोड़कर झोपड़ी के अंदर आ गई थीं। उनकी 18 माह की बेटी निशा रो रही थी।

उन्नाव में 8-10 करोड़ की संपत्ति प्रभावित, बिना लेआउट स्वीकृति के हो रही थी प्लॉटिंग

9 बीघे में काटी जा रहीं दो अवैध कॉलोनियां ध्वस्त





तमसा संकेत, एजेंसी

उन्नाव। उन्नाव में उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण (यूएसडीए) ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने करीब नौ बीघे जमीन पर विकसित की जा रही दो अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त करा दिया। दोनों जगह बिना लेआउट स्वीकृत कराए प्लॉटिंग की जा रही थी।

कार्रवाई में करीब 8 से 10 करोड़ रुपये की संपत्ति प्रभावित होने का अनुमान है। प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक, दोनों कॉलोनियों के संचालकों को पहले कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद ध्वस्तीकरण



आदेश भी पारित किया गया, लेकिन संबंधित लोगों ने प्राधिकरण से स्वीकृति लेने के लिए लेआउट मैप जमा नहीं कराया।

इसके बाद सोमवार को प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण और प्लॉटिंग से जुड़े ढांचों को ध्वस्त करा दिया।

8 से 10 करोड़ बताई जमीन की कीमत

सिटी मजिस्ट्रेट मनोज सिंह ने मंगलवार दोपहर करीब तीन बजे कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। अधिकारियों के अनुसार, दोनों स्थानों की जमीन की अनुमानित कीमत करीब 8 से 10 करोड़ रुपये है। कार्रवाई के बाद बिना स्वीकृत नक्शे के प्लॉटिंग करने वाले कॉलोनाइजरों में खलबली मच गई।

दो स्थानों पर हुई कार्रवाई

पहली कार्रवाई काशीराम कॉलोनी रोड पर की गई, जहां करीब छह बीघे जमीन में अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। दूसरी कार्रवाई काशीराम कॉलोनी से आगे प्रधानमंत्री आवास योजना के पास हुई। यहां करीब तीन बीघे जमीन पर कॉलोनी विकसित की जा रही थी। दोनों जगहों को मिलाकर करीब नौ बीघे जमीन पर अवैध प्लॉटिंग हो रही थी।

प्राधिकरण में पहले जमा कराएं लेआउट

सिटी मजिस्ट्रेट ने कॉलोनी विकसित करने वालों से भी कहा कि प्लॉटिंग शुरू करने से पहले प्राधिकरण में लेआउट जमा कराकर स्वीकृति प्राप्त करें। प्राधिकरण की ओर से नियमानुसार नक्शा पास कराने में आवश्यक सहयोग किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना स्वीकृत लेआउट के प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

खुले तार और रसोई में गंदगी देख भड़के, वार्डन को फटकार

डीएम का छात्रावासों पर छापा

तमसा संकेत, एजेंसी

हरदोई। हरदोई जिलाधिकारी अनुनय झा ने मंगलवार दोपहर करीब 1:30 बजे बावन रोड स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक छात्रावास और जीआईसी परिसर स्थित राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई छात्रावासों में अव्यवस्थाएं मिलने पर डीएम ने नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। राजकीय पॉलिटेक्निक छात्रावास में डीएम को गंदगी, बिजली के खुले तार और पर्याप्त रोशनी नहीं होने जैसी समस्याएं मिलीं। रसोई की स्थिति बेहद खराब मिलने पर जिलाधिकारी ने वार्डन अतुल श्रीवास्तव को फटकार लगाई।





उन्होंने निर्देश दिया कि छात्रों को स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाए। डीएम ने छात्रावास में प्रकाश व्यवस्था बेहतर करने, बिजली के खुले तारों को सुरक्षित कराने, खिड़कियों पर जाली लगवाने और खराब दरवाजों की मरम्मत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानाचार्य कविता त्रिपाठी को नियमित निरीक्षण करने और छात्रावास के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रस्ताव शासन को भेजने को कहा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और शुद्ध भोजन उपलब्ध कराने के लिए 'को-ऑपरेटिव मेस' संचालित करने की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त मजिस्ट्रेट मयंक कुंडू, जिला समाज कल्याण अधिकारी अवनीश कुमार और जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी विनीत कुमार तिवारी मौजूद रहे।



पिछड़ा वर्ग छात्रावास की व्यवस्था मिली ठीक

इसी पॉलिटेक्निक परिसर में स्थित पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के बालक छात्रावास का भी डीएम ने निरीक्षण किया। यहां भोजन, शौचालय और साफ-सफाई की व्यवस्था संतोषजनक मिली। व्यवस्थाएं दुरुस्त मिलने पर जिलाधिकारी ने संतोष व्यक्त किया। जीआईसी परिसर स्थित राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास के निरीक्षण में सफाई व्यवस्था में लापरवाही सामने आई। इस पर डीएम ने सफाई कर्मचारी को कड़ी फटकार लगाई।

बाराबंकी में बाढ़ राहत सामग्री वितरण में धांधली पकड़ी

20 किलो की जगह 8-10 किलो भूसा देने का आरोप

तमसा संकेत, एजेंसी

बाराबंकी। बाराबंकी में रामनगर तहसील क्षेत्र के हेतमापुर में बाढ़ राहत सामग्री वितरण में अनियमि-तता का मामला सामने आया है। घाघरा नदी के उफान से प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ पीड़ित किसानों को पशु चारे के रूप में निर्धारित मात्रा से कम भूसा दिए जाने की शिकायत सामने आई। मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे कारागार राज्यमंत्री एवं प्रभारी मंत्री सुरेश राही के निरीक्षण के दौरान मामले का खुलासा हुआ। जानकारी के मुताबिक हेतमापुर बंधे पर बनाए गए बाढ़ राहत शिविर में किसानों को पशु चारे के लिए भूसा वितरित किया जा रहा था। आरोप है कि मौके पर किसानों को करीब 8 से 10 किलोग्राम भूसा दिया जा रहा था, जबकि वितरण रजिस्टर में प्रति किसान 20 किलोग्राम भूसा दर्ज किया जा रहा था। प्रभारी मंत्री



सुरेश राही राहत शिविर का निरीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर एक किसान के हाथ में मौजूद भूसे की बोरी पर पड़ी। मंत्री ने किसान से बोरी में मौजूद भूसे की मात्रा के बारे में पूछा। किसान ने बताया कि बोरी में करीब 8 से 10 किलोग्राम ही भूसा है। इसके बाद मंत्री ने वितरण काउंटर पर रखे रजिस्टर की जांच कराई। रजिस्टर में उसी किसान के नाम पर 20 किलोग्राम भूसा वितरित किए जाने की एंट्री दर्ज मिली। इस पर मंत्री ने नाराजगी जताते हुए मौके पर मौजूद अधिकारियों से जवाब मांगा।

फैसला : ₹500 से ₹600 हुआ दैनिक भत्ता, डीएम-एमएलए की मौजूदगी में लाइव प्रसारण देखा

पीआरडी जवानों का भत्ता बढ़ा, कैशलेस इलाज शुरू होगा

तमसा संकेत, एजेंसी

उन्नाव। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों के लिए आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़े दो अहम फैसले लिए हैं। अब पीआरडी जवानों को ड्यूटी के लिए प्रतिदिन 600 रुपए भत्ता मिलेगा। पहले यह राशि 500 रुपए थी। इसके साथ ही पीआरडी स्वयंसेवकों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की गई है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोरखपुर में आयोजित पीआरडी जवानों के सम्मेलन में कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण उन्नाव के विकास भवन सभागार में किया गया। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग की ओर से आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता



जवानों और आश्रितों को कैशलेस इलाज

मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू होने से पीआरडी स्वयंसेवकों के साथ उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को भी इलाज की सुविधा मिलेगी। इससे बीमारी या उपचार के दौरान होने वाले खर्च का आर्थिक बोझ कम होगा और जवानों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी।



विधायक ने फैसलों को बताया महत्वपूर्ण

मोहान विधायक ब्रजेश रावत ने भी सरकार के फैसलों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ड्यूटी भत्ते में बढ़ोतरी और कैशलेस चिकित्सा सुविधा से पीआरडी जवानों और उनके आश्रितों को सीधा लाभ मिलेगा। दोनों फैसले जवानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और उनके कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने की। मोहान विधायक ब्रजेश रावत भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने सरकार के फैसलों पर पीआरडी जवानों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पीआरडी जवान कानून-व्यवस्था और विभिन्न प्रशासनिक व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कार्यक्रम में अधिकारियों और बड़ी संख्या में पीआरडी जवानों ने मुख्यमंत्री का संबोधन लाइव सुना। सरकार के फैसले के तहत ड्यूटी मते में प्रतिदिन 100 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इससे नियमित रूप से ड्यूटी करने वाले जवानों की आय में सीधा इजाफा होगा। जवानों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया।

डीएम ने किसानों की आय बढ़ाने के दिए निर्देश

उन्नाव में आत्मा गवर्निंग बोर्ड बैठक में आधुनिक तकनीक अपनाने पर जोर

तमसा संकेत, एजेंसी

उन्नाव। उन्नाव में किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए आधुनिक कृषि तकनीकों, वैज्ञानिक पद्धतियों और नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। मंगलवार दोपहर कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी घनश्याम मीना की अध्यक्षता में कृषि प्रौद्योगिकी अभिकरण (आत्मा) गवर्निंग बोर्ड की बैठक हुई। इसमें सदर विधायक पंकज गुप्ता भी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य किसानों को प्रशिक्षण, तकनीकी जानकारी और सरकारी योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचाना था। कृषि विभाग की सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना के तहत इन रणनीतियों पर



विस्तार से चर्चा की गई। उप निदेशक कृषि रवि चंद प्रकाश ने आत्मा योजना के तहत संचालित और प्रस्तावित कृषि प्रसार गतिविधियों की जानकारी दी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आत्मा योजना के माध्यम से अधिक से अधिक किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, प्रशिक्षण, प्रदर्शन और किसान गोष्ठियों जैसे उपयोगी कार्यक्रमों से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक तकनीकों और नवाचार को बढ़ावा देकर किसानों की आय में वृद्धि की जा सकती है। डीएम ने विशेष रूप से किसानों को जैविक खेती और नवीन कृषि तकनीकों के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि विकासखंड स्तर पर नियमित रूप से किसान गोष्ठियां, फार्मर स्कूल, प्रशिक्षण और प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, ताकि किसान नई तकनीकों को समझकर उन्हें अपनी खेती में अपना सकें। जिलाधिकारी ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से शत-प्रतिशत आच्छादित किया जाए।

सम्पादकीय

भाजपा की नई टीम



अंततः भाजपा के नए अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम घोषित हो गई। इस टीम के गठन की प्रतीक्षा लंबे समय से की जा रही थी। कुछ इसी तरह मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार की भी प्रतीक्षा हो रही थी। नितिन नवीन टीम की घोषणा के बाद यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या अब मंत्रिमंडल में भी विस्तार होगा? यह प्रश्न इसलिए उठेगा, क्योंकि हाल के समय में कुछ चेहरे मंत्रिमंडल से बाहर हुए हैं।

इनमें प्रमुख हैं धर्मेंद्र प्रधान। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल के कई चेहरे पुराने पड़ चुके हैं। तथ्य यह भी है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को फिर से कोषाध्यक्ष बनाया गया है। चूंकि वह पहले भी मंत्री रहने के साथ कोषाध्यक्ष रह चुके हैं, इसलिए वे आगे भी दोनों पद संभाल सकते हैं। जो भी हो, उचित तो यही होगा कि संगठन को नए सिरे से गठित किए जाने के बाद मंत्रिमंडल में भी विस्तार और फेरबदल किया जाए, ताकि उसमें नई ऊर्जा का संचार हो सके। ध्यान रहे जब किसी समूह का नए सिरे से गठन होता है तो कुछ चेहरे ही नहीं बदलते, बल्कि उसकी कार्यशैली और प्राथमिकताएं भी बदलती हैं।

पता नहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल होगा या नहीं, लेकिन इतना अवश्य है कि भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम के समक्ष जनता से जुड़ाव बढ़ाने और अपेक्षाओं पर खरा उतरने की चुनौती है। उनकी टीम में नए और पुराने, दोनों ही चेहरे हैं। यह दिखाता है कि युवाओं और अनुभवी लोगों में संतुलन बैठाने के साथ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचने की कोशिश की गई है और युवाओं एवं महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। ऐसा करना समय की मांग है।

भाजपा की नई टीम में महिलाओं के साथ युवाओं को खास तौर पर आगे किया गया है। इनमें से कुछ तेजतर्रार चेहरे हैं। उन्हें आगे लाना इसलिए आवश्यक था, क्योंकि जहां महिलाएं एक नया और प्रभावी वोट बैंक हैं, वहीं युवा और विशेष रूप से जेन-जी पीढ़ी सबके एजेंडे में हैं। भाजपा की नई टीम को केवल नए अध्यक्ष की टीम कहना सही नहीं होगा। इस टीम में प्रधानमंत्री मोदी की छाप दिख रही है, जो समय की नब्ज भांपने और उसके अनुकूल फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं।

भाजपा की नई टीम के सामने जो अनेक चुनौतियां हैं, उनमें सबसे बड़ी चुनौती नैरेटिव बदलने की है। काकरोच जनता पार्टी के उभार के साथ ही विपक्ष ने संसद के मानसून सत्र को जिस तरह चलने नहीं दिया, उससे इसकी आवश्यकता महसूस हो रही है कि भाजपा को सरकार एवं संगठन के जरिये अपने विरोधी नैरेटिव का प्रतिकार करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। इसमें एक बड़ी भूमिका इंटरनेट मीडिया की होगी। यह अच्छा है कि इंटरनेट मीडिया विभाग में नए चेहरे दिख रहे हैं।

नितिन नवीन की नई टीम नई ऊर्जा और नया संतुलन



> पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया जाना भी उल्लेखनीय है। यह जिम्मेदारी बताती है कि संगठन में राजनीतिक अनुभव के साथ प्रशासनिक, आर्थिक और पेशेवर दक्षता को भी महत्व दिया जा रहा है।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा के साथ यह संकेत दे दिया है कि भाजपा अब संगठन को केवल पदों के पुनर्विन्यास के रूप में नहीं, बल्कि आने वाले राजनीतिक दौर की आवश्यकताओं के अनुरूप नए सिरे से गढ़ने की दिशा में आगे बढ़ रही है। 17 अगस्त 2026 को घोषित नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महासचिव और 16 राष्ट्रीय सचिवों सहित संगठन के विभिन्न स्तरों पर व्यापक परिवर्तन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नई टीम को संगठनात्मक अनुभव, ऊर्जा और जमीनी जुड़ाव का मिश्रण बताया है। इस टीम को समझने के लिए इसे केवल 'कौन आया और कौन गया' के चश्मे से देखना पर्याप्त नहीं होगा। इसके पीछे भाजपा की दीर्घकालीन संगठनात्मक रणनीति, सामाजिक समीकरणों की समझ और आने वाले चुनावों की राजनीतिक चुनौतियों को पढ़ना अधिक महत्वपूर्ण है। नितिन नवीन की टीम का सबसे बड़ा संदेश है-अनुभव को हटाकर युवा ऊर्जा नहीं लाई गई है, बल्कि अनुभव के साथ नई ऊर्जा को जोड़ा गया है। यही संतुलन किसी बड़े राजनीतिक संगठन को गतिशील बनाता है। राम माधव की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में वापसी इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। संगठन, वैचारिक संवाद और रणनीतिक राजनीति की उनकी समझ भाजपा के लिए उपयोगी हो सकती है। वसुंधरा राजे सिंधिया, डी. पुरंदेश्वरी, बैजयंत पांडा, तीरथ सिंह रावत और अन्य वरिष्ठ नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देकर यह स्पष्ट किया गया है कि नितिन नवीन ने वरिष्ठता और अनुभव को किनारे नहीं किया है। यह उस संगठनात्मक सोच का प्रमाण है जिसमें पुराने अनुभव को नई परिस्थितियों के अनुरूप इस्तेमाल करने की कोशिश दिखाई देती है। दूसरी ओर स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी देना भी केवल एक व्यक्ति की वापसी नहीं है। स्मृति ईरानी का राजनीतिक व्यक्तित्व आक्रामक संवाद, महिला मतदाताओं से जुड़ाव और राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी राजनीतिक संप्रेषण से जुड़ा रहा है। उनकी वापसी भाजपा के लिए राजनीतिक संदेश और संगठनात्मक उपयोगिता-दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। उनके साथ विनोद तावड़े, सुनील बंसल जैसे संगठनात्मक अनुभव रखने वाले नेताओं को महासचिव की जिम्मेदारी मिलना संगठन और चुनावी प्रबंधन के बीच बेहतर तालमेल की ओर संकेत करता है।

बी. एल. संतोष का राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बने रहना संगठन की निरंतरता को सुनिश्चित करता है। अर्थात् नितिन नवीन ने पूरी तरह से 'पुराना हटाओ, नया लाओ' की नीति नहीं अपनाई, बल्कि जहां निरंतरता आवश्यक थी वहां उसे बनाए रखते हुए परिवर्तन के लिए पर्याप्त जगह बनाई है। नई टीम का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष सामाजिक और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व है। भाजपा के लिए अब राजनीति केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है, समाज के अलग-अलग वर्गों में संगठन की स्वीकार्यता और पहुंच बढ़ाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। नई टीम में महिलाओं, विभिन्न सामाजिक समुदायों, उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत तक के प्रतिनिधित्व को स्थान दिया गया है। रिपोर्टों के अनुसार टीम में महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों को भी उल्लेखनीय जगह मिली है।

यहां एक और महत्वपूर्ण संकेत दिखाई देता है-भाजपा अब केवल अपने परंपरागत समर्थक वर्ग से संवाद करने के बजाय नए मतदाता समूहों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। युवा, प्रथम बार मतदान करने वाली पीढ़ी, शहरी पेशेवर, तकनीक से जुड़े वर्ग और महिलाओं की राजनीतिक आकांक्षाएं आज चुनावी परिणामों को प्रभावित करती हैं। इसलिए संगठन में ऐसे चेहरों की आवश्यकता है जो केवल राजनीतिक भाषण न दें, बल्कि बदलते समाज की भाषा समझें। भाजपा की नई टीम में इस दिशा का प्रयास स्पष्ट दिखाई देता है। विशेष रूप से युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के स्तर पर किए गए बदलाव इस बात का संकेत हैं कि संगठन भविष्य के मतदाता को आज से ही संबोधित करना चाहता है। जेन-जी को केवल सोशल मीडिया की पीढ़ी मानना भूल होगी। यह पीढ़ी रोजगार, तकनीक, उद्यमिता, पारदर्शिता, राष्ट्रवाद, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अवसरों को लेकर अलग तरह की अपेक्षाएं रखती है। भाजपा यदि इस पीढ़ी से वास्तविक संवाद स्थापित कर पाती है तो उसका लाभ केवल आगामी चुनाव में नहीं, बल्कि 2030 और 2040 के दशक की राजनीति में भी मिल सकता है। नई टीम का सबसे बड़ा राजनीतिक परीक्षण हालांकि उत्तर प्रदेश और अन्य चुनावी राज्यों में होगा। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में संगठन की मजबूती का सीधा असर राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ता है। आगामी चुनावों की दृष्टि से भाजपा के सामने केवल सत्ता विरोधी भावनाओं का मुकाबला करने की चुनौती नहीं है, बल्कि विपक्ष के बदलते गठजोड़, जातीय समीकरण, युवाओं की आकांक्षाओं और स्थानीय मुद्दों को भी साधना है। इसलिए राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना चुनावी दृष्टि से स्वाभाविक रणनीति है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि नई टीम का उद्देश्य केवल 2026-27 के चुनाव नहीं हो सकते। भाजपा की दृष्टि निश्चित रूप से 2029 के लोकसभा चुनाव और उससे आगे तक जाती है। 'विकसित भारत 2047' का लक्ष्य तभी राजनीतिक और सामाजिक आधार प्राप्त कर सकता है जब पार्टी संगठन निरंतर नई पीढ़ी को अपने साथ जोड़ता रहे। इसलिए नितिन नवीन की टीम को एक प्रकार से 2029 की तैयारी और 2047 की राजनीतिक-संगठनात्मक नींव के रूप में भी देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के स्तर पर भी आने वाले समय में परिवर्तन या विस्तार की अटकलें स्वाभाविक हैं, विशेषकर जब सरकार को आगामी राज्यों के राजनीतिक समीकरणों और प्रशासनिक प्राथमिकताओं को साथ लेकर चलना है। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में अभी किसी विशेष व्यक्ति की नियुक्ति को निश्चित मानना उचित नहीं होगा। अनुराग ठाकुर जैसे अनुभवी नेताओं के संभावित भविष्य की चर्चा राजनीतिक हलकों में हो सकती है, पर अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री और भाजपा नेतृत्व पर निर्भर करेगा। नरेन्द्र मोदी की राजनीति में संगठन और सरकार के बीच नई जिम्मेदारियों के माध्यम से ऊर्जा पैदा करने की परंपरा रही है, इसलिए भविष्य में कोई महत्वपूर्ण बदलाव हो तो उसे आश्चर्य के बजाय व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जाना चाहिए।

ललित गर्ग

यह ठीक है कि जन...

कमलेश पांडेय

आखिर जन सुराज पार्टी और लोजपा रामविलास के बीच पक रही सियासी खिचड़ी के निहितार्थ क्या हैं?



बिहार में जन सुराज पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक प्रशांत किशोर और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बीच जो राजनीतिक खिचड़ी पकने की चर्चा है, वह उत्तरप्रदेश की राजनीति से अभिप्रेरित है। चूंकि प्रशांत किशोर मशहूर चुनावी रणनीतिकार भी हैं और लगभग सभी प्रमुख पार्टियों के रणनीतिक घाटों की पानी का स्वाद चख चुके हैं, इसलिए उनसे जुड़ी इस आशय की चर्चा भी अनायास नहीं है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सामाजिक न्याय क्रांति और मंडल बनाम कमंडल की मतलबी राजनीति की कड़ी में जहां उत्तरप्रदेश में चार-चार बार दलित नेत्री सुश्री मायावती को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और उनकी बहुजन समाज पार्टी तीन बार गठबंधन के तहत और एक बार पूर्ण बहुमत से यूपी की सत्ता में आई। लेकिन बिहार में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, जदयू के हुक्मरान नीतीश कुमार ने लोजपा के राम विलास पासवान और उनके पुत्र चिराग पासवान को कभी पूर्ण रूप से उभरने ही नहीं दिया और गठबंधन में भी कमजोर बनाए रखा।

यही वजह है कि बिहार में नए जमाने की राजनीति के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान के साथ गठबंधन की सम्भवनाओं को हवा दिलवाकर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जनता दल यूनाइटेड के सुप्रीमो नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव के समक्ष एक तगड़ी चुनौती पेश करने की अपनी मंशा उजागर कर दी है। चिराग पासवान जिस तरह से खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान करार देते हैं, इससे उनकी भी बेचैनी बढ़ेगी हो।

यह ठीक है कि जन सुराज पार्टी और लोजपा रामविलास के बीच किसी औपचारिक गठबंधन की सार्वजनिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। लेकिन अगस्त 2026 की ताजा राजनीतिक हलचल को देखें तो दोनों के बीच संभावित सियासी तालमेल की चर्चा को महज अफवाह मानकर खारिज करना भी जल्दबाजी होगी। क्योंकि हाल की रिपोर्टों में दोनों के करीब आने और भाजपा-राजद से अलग एक संभावित धुरी की चर्चा सामने आई है। इससे एनडीए की राजनीति में चिराग पासवान का रुतबा बढ़ना भी स्वाभाविक है। फिर भी यदि चिराग पासवान को दलित मुख्यमंत्री बनाने के स्वप्न प्रशांत किशोर यदि दिखाते हैं, या फिर उपमुख्यमंत्री पद का भी सियासी चारा डालते हैं तो मिशन 2029 के संसदीय चुनाव और 2030 के विधानसभा चुनावों को लेकर एनडीए और महागठबंधन के हाथपांव फूलना स्वाभाविक है।

पहला, लोजपा युवराज चिराग पासवान के लिए यह NDA के भीतर दबाव की राजनीति हो सकती है, क्योंकि चिराग पासवान पहले भी सीट बंटवारे और NDA के भीतर अपनी राजनीतिक हैसियत को लेकर स्वतंत्र रुख दिखाते रहे हैं। 2025 में भी उनके प्रशांत किशोर से संभावित संपर्क की खबरें सामने आई थीं। इसलिए सियासत में हर खुली हुई सम्भवनाओं और उससे बनने बिगड़ने वाली हवा से इंकार नहीं किया जा सकता है।

दूसरा, जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के लिए लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान एक महत्वपूर्ण सामाजिक-पॉलिटिकल पुल हो सकते हैं। ऐसा इसलिए कि

जन सुराज अपने को BJP और RJD—दोनों से अलग विकल्प के रूप में स्थापित करना चाहता है। अब बांकीपुर में किशोर की जीत ने उन्हें सिर्फ आंदोलनकारी नहीं, बल्कि क्षेत्रीय चुनावी ताकत के रूप में भी स्थापित किया है। तीसरा, सबसे दिलचस्प संभावना है—'माइनस BJP, माइनस RJD' राजनीति। यानी कि ताजा राजनीतिक चर्चाओं में इसी तरह के पुनर्संयोजन की संभावना उठ रही है। इसका अर्थ होगा कि चिराग पासवान अपना दलित/पासवान प्रभाव और जन सुराज पार्टी अपना युवा, गैर-पारंपरिक तथा शहरी-मध्यवर्गीय आधार जोड़ने की कोशिश करे। दोनों ने यदि रणनीतिक रूप से सवर्णों को तरजीह दी तो भाजपा/कांग्रेस के लिए यह किसी झटके की तरह होगा।

लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दोनों की राजनीतिक जरूरतें अलग अलग हैं। चाहे चिराग पासवान हों या प्रशांत किशोर, दोनों अपना स्वतंत्र राजनीतिक स्पेस बढ़ाना चाहते हैं, साथ ही खुद को तीसरे विकल्प के रूप में स्थापित करना चाहते हैं।

प्रदेश में निराश्रित गोवंश संरक्षण से संवर्धन तक, बनी आत्मनिर्भरता और ग्रामीण रोजगार की नई डगर

उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गोवंश का सदियों से महत्वपूर्ण स्थान रहा है। पशुपालन केवल कृषि का सहायक व्यवसाय नहीं, बल्कि ग्रामीण परिवारों की आजीविका, जैविक खेती और स्थानीय अर्थव्यवस्था का भी आधार रहा है। ऐसे में निराश्रित गोवंश का संरक्षण, उनके भरण-पोषण की व्यवस्था तथा गोवंश आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना एक बड़ी सामाजिक और प्रशासनिक आवश्यकता है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश के मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निराश्रित गोवंश संरक्षण नीति-2019 लागू कर गोवंश के संरक्षण, संवर्धन और जनभागीदारी को एक साथ जोड़ते हुए व्यापक व्यवस्था विकसित की है। सरकार की इस पहल का उद्देश्य केवल निराश्रित गोवंश को आश्रय देना नहीं, बल्कि उनके संरक्षण के साथ किसानों की फसलों को छुट्टा पशुओं से होने वाली क्षति से बचाना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना तथा गोबर और गोमूत्र से उपयोगी उत्पाद तैयार कर गो आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करना भी है।

7,386 गो-आश्रय स्थलों में संरक्षित हैं 12.37 लाख से अधिक गोवंश

निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए प्रदेश में व्यापक आधारभूत ढांचा तैयार किया गया है। वर्तमान में 6,335 अस्थाई गोआश्रय स्थल, 488 गोवंश वन्य विहार/वृहद गो संरक्षण केन्द्र, 242 कांजी हाउस तथा 321 कान्हा गोशालाएं, अर्थात कुल 7,386 गो-आश्रय स्थलों में लगभग 12,37,694 गोवंश संरक्षित किए गए हैं। इन आश्रय स्थलों के माध्यम से निराश्रित गोवंश को सुरक्षित स्थान, चारा, पानी और आवश्यक देखभाल उपलब्ध कराई जा रही है। इससे एक ओर गोवंश के संरक्षण को मजबूती मिली है, वहीं दूसरी ओर किसानों की फसलों को छुट्टा पशुओं से होने वाले नुकसान को दूर करने में भी मदद मिली है।

मा0 मुख्यमंत्री सहभागिता योजना से पशुपालकों को मिला सहारा

प्रदेश में गोवंश संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़ने के लिए मा0 मुख्यमंत्री सहभागिता योजना तथा पोषण मिशन के अंतर्गत भी महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। इसके तहत अब तक 1,14,481 पशुपालकों को 1,84,227 गोवंश सुपुर्द किए जा चुके हैं। इस व्यवस्था से संरक्षित गोवंश को परिवार आधारित देखभाल का अवसर मिलता है और पशुपालकों को भी पशुपालन के माध्यम से अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों से जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार सरकारी संरक्षण व्यवस्था और जनभागीदारी के बीच एक प्रभावी समन्वय स्थापित हुआ है। प्रदेश सरकार ने सुपुर्दगी में प्राप्त गोवंश के भरण पोषण के लिए प्रति गोवंश धनराशि बढ़ाते हुए रू0 1500 प्रति माह कर दिया है।

संरक्षित गोवंश के बेहतर भरण-पोषण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने पूर्व निर्धारित 30 रुपये प्रति गोवंश प्रतिदिन की धनराशि को बढ़ाकर 50 रुपये प्रति गोवंश प्रतिदिन कर दिया है। वर्तमान में संरक्षित गोवंश के भरण-पोषण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिदिन लगभग 7 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा रहा है। इस बढ़ी हुई सहायता से गो-आश्रय स्थलों में चारे एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में मदद मिल रही है।

कोई प्रतिस्पर्धा नहीं

आज के इस भौतिक चकाचौंध के युग में हम देखते हैं कि सभी क्षेत्रो में सभी जगह में कैसे ही हो ,किसी भी तरीक़े से हो ,आगे बढ़ने की अंधाधुँध प्रतिस्पर्धा चल पड़ी हैं ।आधुनिकता का दबाव,प्रतिस्पर्धा का प्रभाव,ज्यादा से ज्यादा आमदनी की चाह भी रहती हैं ।कहीं - कहीं इस प्रतिस्पर्धा के नकारात्मक परिणाम हमको अलग ही स्वरुप में देखने को मिलते हैं । ऐसा नहीं हैं कि प्रतिस्पर्धा ख़राब होती हैं बल्कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा ,सकारात्मक परिणामस्वरुप आगे बढ़ने के लियें सदैव प्रोत्साहित करती रहती है। इस प्रोत्साहन से आगे बढ़ने के लियेसदैव ऊर्जा का संचार होता रहता है।व कितनी भी कठिनाई हो उसमें डगमगाता नहीं हैं । निरन्तर कन्धा से कन्धा मिलाकर चलता रहता हैं व सबकी अच्छाईयो को ही देखता रहता हैं । जुनून, लग्न व परिश्रम से लक्ष्य की और बढ़ता रहता है । यह कोई प्रतिस्पर्धा नही होती बल्कि सफलता ही सफलता को प्राप्त करता रहता हैं । पढ़-लिखकर कैरियर बनाना कोई भी क्षेत्र में तो व्यवहारिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व आजीविका चलाने के लिए आवश्यक होता है। लेकिन दिन-रात सब कुछ भूलकर सिर्फ और सिर्फ़ इस भौतिकता की अंधी दौड़ में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा की होड़ बुरी है । वह सभी तरीक़े से सुख-चैन सब कुछ छीन लेती है ।आदमी का जीना दुश्वार हो जाता है,कहीं भी मानसिक शांति नहीं पा सकता ,ऐसे में मनुष्य । विवेक से संतुलन बिठाकर किये जाने से कोई भी काम में मनुष्य सफलता पाकर तन से,मन से स्वस्थ रहता हुआ आनंदमय जीवन जी सकता है । सफलता का मंत्र है विवेक से संतुलन बिठाकर काम करना व प्रतिस्पर्धा की नसोचना। हर स्वभाव पर नहींहोता किसी दूसरे का अधिकार व इसको हर जीव करता है स्वीकार। उसके अनुसार ही होता व्यवहार। एक ही घटना का होता सब पर अलग - अलग असर। प्रतिस्पर्धा या उस पर ध्यान केंद्रित करने की अपनी नजर। तब खुशी की खोज पर चल रही डगर। बहुत खुब अल्फाज मे बोला हैं किसी ने की खुशी का कभी पता नही बता सकता हैं कोई कायर। भीतर जाने के रास्ते से अनजान या होंडा - होड़ में भटक रहा बाहर । दया और परोपकार रहते उसके भीतर। ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा रहती बाहर। बाहर या भीतर, किसी एक रास्ते पर देख लो चलकर। खुशी का पता या सही प्रतिस्पर्धा या पाने की चाहत कर, निष्ठा और श्रद्धा व सदाचार के अस्तित्व को लेकर करे प्रतिस्पर्धा।

› प्रदीप छाजेड़

जरा हटके

इस डिजिटल ...

डॉ0 सीमा गुप्ता

गाजियाबाद में 'प्रोजेक्ट समर्थ' से संवर रहा दिव्यांग बच्चों का भविष्य



प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सर्वांगीण विकास और सामाजिक न्याय की अवधारणा को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से संचालित 'प्रोजेक्ट समर्थ' समावेशी शिक्षा और बाल कल्याण के क्षेत्र में एक युगांतरकारी पहल साबित हुआ है। प्रदेश के दूर-दराज के क्षेत्रों में निवासरत दिव्यांग बच्चों (चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स) को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने, उनके सर्वांगीण पुनर्वास और उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए शुरू किया गया यह व्यापक अभियान अब अपने प्रभावी क्रियान्वयन के दम पर सकारात्मक सामाजिक बदलाव की मिसाल बन चुका है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की मूल नीति पर आधारित यह परियोजना विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के वैज्ञानिक चिन्हांकन से लेकर उनके डिजिटल ट्रैकिंग, शैक्षणिक संवर्धन, स्वास्थ्य परीक्षण, सहायक उपकरण वितरण एवं वित्तीय सहायता को एक एकीकृत मंच पर सफलतापूर्वक उपलब्ध करा रही है। समावेशी समाज के निर्माण की दिशा में यह व्यवस्था अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रही है। प्रोजेक्ट समर्थ के सफल क्रियान्वयन की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी तकनीक-आधारित पारदर्शी निगरानी प्रणाली है। सरकार द्वारा विकसित किए गए विशेष मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से प्रदेश भर के विद्यालयों तथा अब तक नामांकित न हो सके दिव्यांग बच्चों का व्यापक डिजिटल डेटाबेस तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत न्याय पंचायत और ब्लॉक स्तर पर तैनात विशेष शिक्षकों द्वारा घर-घर जाकर शून्य से चौदह वर्ष तथा माध्यमिक स्तर के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का पारदर्शी चिन्हांकन सुनिश्चित किया गया है।

इस डिजिटल प्रणाली पर प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट दिव्यांगता का प्रकार, गंभीरता का स्तर, पारिवारिक पृष्ठभूमि और शैक्षणिक स्थिति का रियल-टाइम डेटा निरंतर दर्ज किया जा रहा है। इस सुदृढ़ व्यवस्था से न केवल योजनाओं के दोहरेपन पर पूर्ण रोक लगी है, बल्कि वास्तविक लाभार्थियों तक सरकारी सुविधाओं, योजनाओं और छात्रवृत्तियों की समयबद्ध पहुंच भी सुनिश्चित हुई है। परियोजना के अंतर्गत संचालित व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना (इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान) व्यवस्था अत्यंत व्यावहारिक और उपयोगी सिद्ध हुई है। इसके माध्यम से प्रत्येक दिव्यांग बच्चे की सीखने की व्यक्तिगत क्षमता, बौद्धिक स्तर और विशिष्ट शारीरिक आवश्यकताओं के अनुरूप अलग से शैक्षणिक प्रारूप तैयार किया जाता है, जिससे बच्चों के सीखने की गति में निरंतर सुधार दर्ज हो रहा है।

जो बच्चे गंभीर शारीरिक अक्षमता अथवा स्वास्थ्यगत कारणों से नियमित रूप से विद्यालय आने में असमर्थ हैं, उनके लिए गृह-आधारित शिक्षा की ठोस व्यवस्था लागू की गई है। इस प्रक्रिया में विशेष शिक्षक नियमित अंतराल पर बच्चों के घर जाकर अध्ययन, उपचारात्मक शिक्षण और आवश्यक थेरेपी सहायता प्रदान कर रहे हैं, जिससे कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहे।

शैक्षणिक सामग्री के आधुनिकीकरण के क्रम में दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल पाठ्यपुस्तकों, स्क्रीन-रीडिंग सॉफ्टवेयर, डिजिटल उपकरणों और टॉकिंग बुक्स की सुलभता सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही मूक-बधिर बच्चों के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा पर आधारित डिजिटल शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराकर उनकी समझ और अभिव्यक्ति क्षमता को सशक्त बनाया गया है। दिव्यांग विद्यार्थियों की नियमित विद्यालयी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने वित्तीय और लॉजिस्टिक प्रोत्साहनों का एक पारदर्शी तंत्र स्थापित किया है। गंभीर दिव्यांगता से प्रभावित बच्चों को घर से विद्यालय लाने और ले जाने के लिए अभिभावकों अथवा सहायकों को एस्कॉर्ट अलाउंस (मार्ग व्यय भत्ता) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे बैंक खातों में प्रेषित किया जा रहा है। दिव्यांग बालिकाओं की शिक्षा को विशेष प्राथमिकता देते हुए उनके लिए समर्पित स्टाइपेंड और छात्रवृत्ति योजनाओं का निर्बाध वितरण किया जा रहा है। इस निरंतर आर्थिक और सामाजिक संबल के परिणामस्वरूप प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर दिव्यांग बालिकाओं के ड्रॉप-आउट दर में उल्लेखनीय और ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है, जिससे वे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही हैं। शारीरिक और सहायक पुनर्वास के क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के समन्वय से प्रदेश के सभी जनपदों में नियमित रूप से बृहद मेडिकल असेसमेंट कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा परीक्षण के उपरांत बच्चों को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, उन्नत डिजिटल श्रवण यंत्र, ब्रेल किट, कैलिपर्स और प्रोस्थेटिक्स जैसे आवश्यक सहायक उपकरण निःशुल्क प्रदान किए जा रहे हैं।गंभीर दृष्टि अथवा श्रवण दोष से प्रभावित बच्चों के जीवन को सुगम बनाने के लिए आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ चिकित्सालयों में करेक्टिव सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। इन समस्त चिकित्सीय प्रक्रियाओं और उपचार का संपूर्ण वित्तीय भार प्रदेश सरकार द्वारा पूर्ण निष्ठा से वहन किया जा रहा है, जिससे निर्धन परिवारों पर कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ता।

59 साल पुराने मस्जिद-मदरसे पर चला बुलडोजर

2 घंटे में 6 बुलडोजरों से गिराया, पुलिसवालों और सपाइयों के बीच धक्का-मुक्की

एक्शन

तमसा संकेत, एजेंसी

सिद्धार्थनगर। यूपी के सिद्धार्थ-नगर में मंगलवार को एक मस्जिद और मदरसे के आधे से ज्यादा हिस्से को बुलडोजर चलाकर ढहा दिया गया। 59 साल पुराना मस्जिद-मदरसा सरकारी जमीन पर बना था। सुबह 7 बजे SDM और 5 थानों के लगभग 100 पुलिसकर्मी 6 बुलडोजर लेकर पिपरा रामलाल गांव पहुंचे। 14 हजार स्क्वायर फीट में बने मस्जिद-मदरसे के अवैध 9 हजार स्क्वायर फीट हिस्से पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की। इस बीच, डुमरियागंज की सपा विधायक सैय्यदा खातून, सपा जिलाध्यक्ष



लालजी यादव समेत 50 से ज्यादा कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। बुलडोजर एक्शन का विरोध कर नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने रोका तो बहस होने लगी। उनके बीच धक्का-मुक्की भी हुई। करीब आधे घंटे तक इलाके में तनाव बना रहा। बाद में पुलिस ने बैरिकेडिंग कर लोगों को दूर किया और 2 घंटे में आधी मस्जिद, आधे मदरसे, 7 कमरे और एक दुकान को ढहा दिया। मामला जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर डुमरिया-गंज तहसील क्षेत्र का है।

- 6 बुलडोजरों की मदद से दो घंटे मदरसे के आधे से ज्यादा हिस्से को ढहा दिया गया।
- 14 हजार स्क्वायर फीट में 5 हजार स्क्वायर फीट हिस्सा ही वैध था। बाकी 9 हजार स्क्वायर फीट जमीन को कब्जामुक्त कराया गया।

मदरसे में 400 बच्चे पढ़ते थे, 14 अगस्त को कोर्ट ने दिया था आदेश

गांव के लोगों ने बताया- आरबिया जियाउल उलूम मदरसा 1938 में गांव के अंदर बना था।1967 में इसे पीपरा रामलाल गांव की मेन रोड यानी बांसी-डुमरियागंज मार्ग पर शिफ्ट कर दिया गया। मदरसे का निर्माण पहले निजी जमीन पर किया गया। उसके बाद धीरे-धीरे आगे खाली पड़ी सरकारी जमीन पर कब्जा होता चला गया। मदरसे में करीब 400 बच्चे पढ़ते थे।

अफसरों ने बताया- सरकारी रिकॉर्ड में मदरसे की जमीन सिर्फ 5 हजार स्क्वायर फीट ही है। बाकी 9 हजार स्क्वायर फीट जमीन खेल के मैदान के रूप में दर्ज है। 2022 में पांच ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से इस जमीन से कब्जा हटाने के लिए डुमरियागंज तहसीलदार कोर्ट में याचिका दायर की थी।

मामले की सुनवाई के बाद 2023 में बेदखली का आदेश जारी हुआ। आदेश को मदरसे के केयरटेकर अब्दुल सलाम ने 2023 में डीएम कोर्ट में चुनौती दी। 3 साल चली सुनवाई के बाद 14 अगस्त 2026 को डीएम ने तहसीलदार कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए मदरसा पक्ष की याचिका खारिज कर दी। इसके बाद प्रशासन ने जमीन से



अवैध कब्जा हटाने का नोटिस जारी किया। तय समय सीमा में कब्जा न हटाए जाने पर डुमरियागंज SDM विवेकानंद मिश्र, डुमरियागंज के CO बृजेश वर्मा और बांसी के CO सिवेंदु सिंह की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई।

300 से अधिक मंदिरों का कायाकल्प

करोड़ों की परियोजनाओं से संवर रहे सरोजनीनगर के आस्था केंद्र

तमसा संकेत,संवाददाता



लखनऊ। सरोजनीनगर में धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में व्यापक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह के प्रयासों से विधानसभा क्षेत्र के 300 से अधिक मंदिरों में सीएसआर के माध्यम से सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं के लिए मूलभूत सुविधाओं का विस्तार कराया गया है। वहीं प्रमुख एवं प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए करोड़ों रुपये की परियोजनाओं को शासन स्तर से वित्तीय स्वीकृति मिली है। विभिन्न मंदिर परिसरों में आवश्यकता के अनुसार हैंडपंप, सोलर लाइट, श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था, फर्श निर्माण और स्वच्छता संबंधी सुविधाएं विकसित की गई हैं। इसके अलावा रंगाई-पुताई कर मंदिर परिसरों को स्वच्छ और आकर्षक स्वरूप दिया गया है। डॉ. राजेश्वर सिंह के अनुसार मंदिर केवल पूजा-अर्चना के स्थल नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा, आध्यात्मिक मूल्यों और सामाजिक चेतना के केंद्र हैं। इनके संरक्षण से आने वाली पीढ़ियों को अपनी विरासत से जोड़ने में मदद मिलेगी। हरौनी स्थित झाड़ेश्वर महादेव मंदिर के लिए 1.05 करोड़ रुपये, परवर पश्चिम स्थित श्री महादेव जल साईं नाथ शिवधाम महादेवन मंदिर के लिए 98 लाख रुपये, कबीर पंथी दाता साई संत आश्रम के लिए 1 करोड़ रुपये तथा परवर पश्चिम स्थित श्री महादेव झलकारी नाथ मंदिर के लिए 98 लाख रुपये शामिल हैं।

फास्ट न्यूज

50 साल पुराने गंगापुल पर 100 से अधिक गड्ढे

कानपुर। कानपुर का 50 साल पुराना जाजमऊ गंगापुल अब कांपता नजर आता है। कानपुर-उन्नाव को जोड़ने वाले इस पुल पर 100 से अधिक गड्ढे हैं। कई जगह सड़क टूटने से सरिया बाहर निकल आई है। रोज करीब 40 हजार वाहन इसी पुल से गुजरते हैं। गड्ढों से बचने के लिए वाहनों की रफ्तार थम जाती है और जाम की स्थिति बनती है। एनएचएआई अब पुल की मरम्मत के लिए इसे 90 दिन तक बंद करने की तैयारी में है।

युवक की कनपटी पर असलहा सटाकर चलाई गोली

लखनऊ। लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह युवक पर जानलेवा हमला किया गया। मंदिर से दर्शन कर लौट रहे युवक की कनपटी पर बदमाश ने असलहा सटा दिया। इसके बाद फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि युवक बाल-बाल बच गया। घटना के बाद पीड़ित ने ठाकुरगंज थाने में तहरीर दी है। अहमदगंज गऊघाट निवासी रतनलाल गुप्ता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि मंगलवार सुबह करीब 8:30 बजे आन्नदी माता मंदिर से दर्शन कर घर लौट रहे थे।

कांस्टेबल ने पोस्टमार्टम कर्मचारी को लात-घूंसों से पीटा

कानपुर। कानपुर पोस्टमार्टम हाउस में कागज मांगने पर सोमवार देर रात बॉडी रखवाने आए जीआरपी कांस्टेबल ने कर्मचारी की लात-घूंसों से जमकर पिटाई कर दी। कर्मचारी के साथ मारपीट की जानकारी मिलने पर पोस्टमार्टम कर्मियों में आक्रोश फैल गया। कर्मियों ने जीआरपी इंस्पेक्टर पर कार्रवाई की मांग करते हुए काम बंद कर दिया।

फर्जी पहचान से जमीन की रजिस्ट्री कराने वाली महिला गिरफ्तार

तमसा संकेत, एजेंसी



लखनऊ। बिजनौर थाना पुलिस ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर दूसरे की पहचान का इस्तेमाल करते हुए जमीन की रजिस्ट्री कराने और उसी जमीन पर लोन लेने के मामले में वांछित एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार महिला की पहचान नसीम बानो उर्फ नस्सो पत्नी स्व. सदकत हुसैन के रूप में हुई है। वह कथित तौर पर फर्जी नाम मनीषा सिंह के नाम से रजिस्ट्रीकर्ता बनी थी।

पुलिस के अनुसार, इस मामले में 7 अप्रैल 2026 को सौभाग्य एल्डिको उद्यान-2, रायबरेली रोड निवासी मनीषा सिंह की तहरीर पर बिजनौर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि नामजद आरोपियों ने वादिनी की जमीन के साथ धोखाधड़ी करते हुए कूटरचित दस्तावेज तैयार किए और जमीन को फर्जी तरीके से बेचने के साथ ही उस पर लोन भी लिया।

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि कथित मनीषा सिंह की पहचान का इस्तेमाल करते हुए नसीम बानो ने अपने साथियों के साथ मिलकर फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड समेत अन्य दस्तावेज तैयार किए। इसके बाद फर्जी पहचान के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री कराई गई और उसी जमीन पर लोन लिया गया। पुलिस के मुताबिक लोन से प्राप्त धनराशि को आरोपियों ने आपस में बांट लिया।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए डीसीपी दक्षिणी की ओर से दो पुलिस टीमों का गठन किया गया था। तकनीकी एवं मैनुअल साक्ष्यों तथा स्थानीय सूचना तंत्र की मदद से पुलिस ने 18 अगस्त को नसीम बानो उर्फ नस्सो को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया।

3 गोलियां मारीं, पत्नी को मायके ले जाने से नाराज था, प्रतापगढ़ में भीड़ ने बांधकर पीटा

रिटायर्ड फौजी ने बुलेटप्रूफ जैकेट पहनकर साले की हत्या की

तमसा संकेत, एजेंसी



प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में रिटायर्ड फौजी ने सगे साले की हत्या कर दी। वह सुल्तानपुर से साले की मेडिकल स्टोर की दुकान पहुंचा। वहां ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जब तक साला कुछ समझ पाता, तब तक तीन गोलियां उसे लग गईं। वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। आरोपी बुलेटप्रूफ जैकेट पहनकर पहुंचा था। फौजी ने मौके से भागने की कोशिश की। भीड़ ने उसे पकड़ लिया। रस्सी से बांधकर पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह आरोपी फौजी कपिल यादव (43) को भीड़ से बचाया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया। आसपास के लोग साले देवेंद्र यादव (48) को जिला अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फौजी कपिल यादव का पत्नी प्रियंका से विवाद चल रहा था। सोमवार को देवेंद्र अपने जीजा के घर सुल्तानपुर गया। वहां से बहन प्रियंका और बच्चों को साथ ले आया था। इसी बात से कपिल साले से नाराज था। वारदात मंगलवार दोपहर 12 बजे जिला मुख्यालय से 25 किमी दूर कोहंडौर थाना क्षेत्र की है।

ताबड़तोड़ 10 फायर किए

प्रतापगढ़ में मदाफरपुर बाजार में देवेंद्र की मेडिकल स्टोर की दुकान है। सोमवार को वह दुकान पर बैठा था। तभी कपिल सुल्तानपुर से वहां पहुंच गया। वह फौजी की वर्दी में था। दोनों के बीच बहस हुई। कपिल ने धमकाया कि तुम प्रियंका को लेकर कैसे आ गए। इसी दौरान बात बढ़ी तो कपिल ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उसने लाइसेंसी पिस्टल से 10 राउंड फायर किए। तीन गोली कपिल को लगी। एक सिर, दूसरी कमर



- पुलिस को मौके से पिस्टल की मैगजीन और कारतूस के खोखे बरामद किए हैं।
- वारदात के बाद महिलाएं दौड़कर मौके पर पहुंचीं। मृतक के पास बैठकर फूट-फूटकर रोईं।

15 साल पहले हुई थी शादी, 6 महीने से पत्नी से था विवाद

फौजी कपिल (43) की 15 साल पहले प्रियंका से शादी हुई थी। पिछले साल कपिल फौज से रिटायर हो गया था। वह सुल्तानपुर के जिला अस्पताल में गार्ड की नौकरी करने लगा था। 6 महीने से पति-पत्नी में विवाद चल रहा था।

15-20 दिन में लगेंगे शिविर, 10.44 लाख लाभार्थियों को मिली पेंशन

दिव्यांगजन योजनाओं की समीक्षा

तमसा संकेत, संवाददाता



लखनऊ। दिव्यांगजन सशक्ति-करण विभाग की योजनाओं और व्यवस्थाओं की समीक्षा को लेकर मंगलवार को प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने अपने सरकारी कार्यालय में उच्चाधिका-रियों के साथ बैठक की। बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति, दिव्यांगजनों को मिल रही सुविधाओं, पेंशन वितरण, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल योजना और योजनाओं के प्रचार-प्रसार समेत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दिव्यांगजनों की समस्याओं के समाधान में किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए। साथ ही मंडल और जिला स्तर के अधिकारियों के साथ नियमित वर्चुअल बैठकें आयोजित कर योजनाओं की जमीनी स्थिति की निगरानी करने को कहा। नरेन्द्र कश्यप ने मुजफ्फरन-गर के जिलाधिकारी और उपजिलाधिकारी से दूरभाष पर वार्ता कर पांच एकड़ सरकारी भूमि शीघ्र चिन्हित करने को कहा, ताकि परियोजना को आगे बढ़ाया जा सके। बैठक में सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर खर्च होने वाली धनराशि को लेकर भी मंत्री ने अधिकारियों से जवाबदेही तय करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रचार-प्रसार पर खर्च की जाने वाली राशि का नियमित फीडबैक लिया जाए। इससे यह पता चल सकेगा कि किस मद में कितनी धनराशि खर्च हो रही है और प्रचार का अपेक्षित सकारात्मक परिणाम मिल रहा है या नहीं। मंत्री ने तकनीक के मौजूदा दौर को देखते हुए सोशल मीडिया के लिए भी नियमावली तैयार करने के निर्देश दिए।

आवेदन पर कार्रवाई की जानकारी आवेदक को भी मिले

बैठक में नरेन्द्र कश्यप ने कहा कि सरकार और दिव्यांगजनों के बीच संवादहीनता की स्थिति समाप्त होनी चाहिए। विभाग में दिव्यांगजनों की ओर से प्राप्त होने वाले आवेदन और प्रपत्रों पर समयबद्ध एवं उचित कार्रवाई की जाए। साथ ही आवेदनकर्ता को भी उसके आवेदन पर की गई कार्रवाई की जानकारी दी जाए, ताकि उसे अपनी समस्या के निस्तारण की स्थिति के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं की निगरानी केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि अधिकारियों के स्तर से नियमित समीक्षा कर लाभार्थियों तक योजनाओं का वास्तविक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए।





मुजफ्फरनगर में 24 करोड़ से बनेगा समेकित विद्यालय

मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मुजफ्फरनगर में दिव्यांगजनों के लिए समेकित विद्यालय के निर्माण के लिए 24 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। विद्यालय के निर्माण के लिए भूमि चिन्हांकन की प्रक्रिया जल्द पूरी कराने के निर्देश दिए गए हैं।

युवाओं को कौशल के साथ रोजगार से जोड़ने पर जोर

हर महीने होगा ट्रेनिंग पार्टनर्स से संवाद

तमसा संकेत, संवाददाता



लखनऊ। योगी सरकार प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण के साथ रोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ने के लिए कौशल विकास व्यवस्था को लगातार अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और परिणामोन्मुख बना रही है। इसी क्रम में मंगलवार को उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन मुख्यालय में आयोजित 'कौशल समाधान दिवस' पर प्रशिक्षण प्रदाताओं (ट्रेनिंग पार्टनर्स) की समस्याओं को सीधे सुना गया और उनके समयबद्ध समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल, प्रमुख सचिव डॉ. हरिओम तथा मिशन निदेशक पुलकित खरे की उपस्थिति में मिशन अधिकारियों और प्रशिक्षण प्रदाताओं के बीच विस्तृत संवाद हुआ। बैठक में लंबित भुगतान, ट्रेंच भुगतान व्यवस्था, ड्रेस भुगतान, असेसमेंट एवं प्रमाण-पत्र, परफॉर्मेंस गारंटी, नामांकन, प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति, प्लेसमेंट, प्रशिक्षण गुणवत्ता, डिजिटल पोर्टल तथा कार्रवाई से पूर्व स्पष्टीकरण जैसे विषयों पर चर्चा हुई। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि कौशल विकास मिशन का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि प्रदेश के युवाओं को ऐसा वास्तविक कौशल उपलब्ध कराना है। जिससे वे रोजगार प्राप्त कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण प्रदाता सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

विवाद : लखनऊ में पत्नी ने मुंह पर जूतियां मारीं, बोली- सेक्स रैकेट चलाता है

पंचायत सचिव गर्लफ्रेंड के साथ फ्लैट में पकड़ा गया

- गुडंबा इलाके में पति-पत्नी के बीच जमकर विवाद हुआ।
- पत्नी ने पति को कमरे में दूसरी महिला के साथ देख लिया।

तमसा संकेत, एजेंसी



लखनऊ। लखनऊ में पंचायत सचिव को पत्नी ने महिला के साथ फ्लैट में पकड़ लिया। दोनों को साथ देखकर पति-पत्नी के बीच जमकर विवाद हुआ। पत्नी ने महिला से मारपीट की और 5 थप्पड़ मारे। इसके बाद पति के मुंह पर भी 2 जूतियां मारीं। हंगामे की सूचना पर पुलिस पहुंची और मामला शांत कराया। घटना 15 अगस्त की है। इसका वीडियो अब सामने आया है। माल विकासखंड की एक ग्राम पंचायत में सचिव पद पर तैनात अल्सफ बेग कुर्सी रोड स्थित सुलभ आवास के एक फ्लैट में महिला के साथ मौजूद थे। इसकी जानकारी उनकी पत्नी सबा को मिली तो वह मौके पर पहुंच गईं। कुछ देर पति-पत्नी के बीच कहासुनी हुई। फिर मारपीट होने लगी। मामला गुडंबा इलाके का है। आरोप है कि अल्सफ पत्नी और बेटी की देखभाल नहीं करता। वह कई बार उसे जान से मारने की धमकी भी दे चुका है। शादी के बाद से ही वह अक्सर किसी न किसी बहाने देर रात तक घर नहीं लौटता था। पत्नी-बेटी को अकेला छोड़ देता था।गुडंबा इंस्पेक्टर अंजनी कुमार मिश्रा के मुताबिक, 15 अगस्त को सबा को सूचना मिली थी कि उसका पति अल्सफ एक फ्लैट में एक महिला के साथ मौजूद है। सूचना मिलने पर वह कुर्सी रोड स्थित सुलभ आवास के ब्लॉक-बी में पहुंची। वहां अल्सफ एक महिला के साथ मिला। इसके बाद यूपी-112 की टीम दोनों पक्षों को गुडंबा थाने ले आई। सबा ने पति पर उत्पीड़न और मारपीट समेत कई आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी है।

पत्नी बोली- आए दिन पति मारपीट करता है

पत्नी सबा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी शादी अल्सफ बेग से 9 जून, 2021 को हुई थी। अल्सफ ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर तैनात है। आरोप है कि शादी के बाद से ही वह उसके साथ मारपीट करता था। पति के खराब व्यवहार के चलते कुछ समय बाद उसके परिवार वालों ने उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद से वह किराए के मकान में पति के साथ रह रही है। दोनों की ढाई साल की बेटी है।

सरकारी नौकरी का धौंस दिखाकर धमकी देने का आरोप

सबा ने आरोप लगाया कि उसका पति शराब और ड्रग्स लेता है। नशे की हालत में वह पत्नी और बेटी के साथ मारपीट करता है। साथ ही सरकारी नौकरी का धौंस दिखाकर उसे घर से निकालने और दूसरी शादी करने की धमकी देता है। पति के खिलाफ कई बार थाने में शिकायत हुई और दोनों के बीच समझौता भी कराया गया, लेकिन उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया। सबा ने पति पर दूसरी महिलाओं से संबंध रखने और गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने का भी आरोप लगाया है। उसने पति पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप भी लगाया है।

यूपी सरकार का तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर जोर

मैनपुरी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रशासनिक परिषद की छठी बैठक आयोजित

तमसा संकेत, संवाददाता



लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता, संस्थानों के आधारभूत ढांचे और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। इसी क्रम में लोकमाता देवी अहिल्या बाई होल्कर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनपुरी की प्रशासनिक परिषद की छठी बैठक मंगलवार को प्राविधिक शिक्षा मंत्री एवं प्रशासनिक परिषद के अध्यक्ष आशीष पटेल की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में संस्थान की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं, आधारभूत सुविधाओं, वित्तीय मामलों, मानव संसाधन, भर्ती प्रक्रिया, मान्यता एवं संस्थान के आगामी विकास कार्यों सहित विभिन्न एजेंडों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। बैठक में महानिदेशक प्राविधिक शिक्षा सेल्वा कुमारी जे., निदेशक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी प्रो. दीपेंद्र सिंह सहित वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आईआईटी कानपुर, केएनआईटी सुल्तानपुर, आईईटी लखनऊ तथा संस्थान के अधिकारियों एवं शिक्षकों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। बैठक में संस्थान में लेक्चर कॉम्प्लेक्स के निर्माण के प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए निर्धारित समयसीमा में निर्माण कार्य पूरा कराने पर जोर दिया गया। संस्थान में विद्यार्थियों के लिए बेहतर शैक्षणिक वातावरण विकसित करने तथा आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। प्रशासनिक परिषद ने संस्थान में विभिन्न स्वीकृत पदों पर भर्ती प्रक्रिया से संबंधित विषयों पर भी चर्चा की। नए स्वीकृत पदों पर आगे की कार्रवाई शासन स्तर से आवश्यक समन्वय एवं अनुमोदन के बाद करने के निर्देश दिए गए। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि भर्ती एवं मानव संसाधन से संबंधित सभी प्रक्रियाएं शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं मानकों के अनुरूप ही संचालित की जाएं। बैठक में संस्थान की सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं से संबंधित प्रस्तावों पर भी विचार किया गया।

लंबित मांगों पर भारतीय मजदूर संघ का प्रदर्शन

कलेक्ट्रेट में नारेबाजी, डीएम को सौंपा ज्ञापन, जल्द समाधान की मांग

नारेबाजी

तमसा संकेत, एजेंसी

आगरा। लंबे समय से लंबित मांगों के समाधान की मांग को लेकर भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। विभिन्न विभागों से जुड़े कर्मचारियों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को जल्द पूरा किए जाने की आवाज उठाई। प्रदर्शन के बाद संगठन के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री तथा केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ओमप्रकाश ने बताया कि भारतीय मजदूर संघ की ओर से 17 अगस्त को पूरे प्रदेश में लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन और ज्ञापन का



कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आगरा में सोमवार को अवकाश होने के कारण यहां मंगलवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि संगठन का उद्देश्य कर्मचारियों की समस्याओं को सरकार के समक्ष मजबूती से रखना है, ताकि लंबे समय से लंबित मामलों पर जल्द निर्णय हो सके। उन्होंने कहा कि नगर निगम, जलकल, पीडब्ल्यूडी, विश्वविद्यालय, रेलवे और बैंकिंग समेत कई क्षेत्रों के कर्मचारी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। संगठन का प्रयास है कि सभी विभागों में कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार करे।

कई विभागों के कर्मचारी प्रदर्शन में हुए शामिल

प्रदर्शन में जिले के अलग-अलग विभागों और संस्थानों से जुड़े कर्मचारी शामिल हुए। नगर निगम, जलकल, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), विश्वविद्यालय, रेलवे और बैंकिंग सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कर्मचारियों का कहना था कि उनकी कई मांगें वर्षों से संबंधित स्तर पर लंबित हैं, लेकिन बार-बार मांग उठाए जाने के बावजूद अभी तक उनके समाधान की दिशा में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। कर्मचारियों ने कहा कि लंबित मांगों को लेकर सरकार और संबंधित विभागों के अधिकारियों के सामने कई बार समस्याएं रखी जा चुकी हैं। इसके बावजूद ठोस निर्णय नहीं होने से कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है। इसी के चलते भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया गया।

जिलाध्यक्ष ने कहा- वर्षों से चल रही है मांगों पर बातचीत

भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश ने बताया कि संगठन की ओर से पूरे प्रदेश के जिलों में कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ कई वर्षों से विभिन्न मांगों को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक कई मुद्दों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने कहा कि संगठन ने अब ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री और वित्त मंत्री तक कर्मचारियों की समस्याएं पहुंचाने का निर्णय लिया है।



श्रमिकों की समस्याओं के समाधान की मांग

प्रदर्शन के दौरान राधारंजन शर्मा ने कहा कि देश और प्रदेश में श्रमिकों की कई मांगें लंबे समय से लंबित हैं। कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की समस्याएं अलग-अलग हो सकती हैं।

तेंदुए ने महिला की गर्दन दबोची, मौत

गुस्साए ग्रामीणों ने वन विभाग पर पथराव किया

तमसा संकेत, एजेंसी



मुरादाबाद। मुरादाबाद में तेंदुए ने एक महिला का शिकार कर लिया। तेंदुआ ने खेत पर काम कर रही महिला की गर्दन दबोच ली और उन्हें घसीटते हुए गन्ने के खेत में ले गया। साथ काम कर रही महिलाओं की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर मौके पर पहुंचे और शोर मचाया तो तेंदुआ भाग गया, लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। महिला की पहचान ब्रह्मो देवी (60) के रूप में हुई। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम को भी ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। गुस्साए ग्रामीणों ने टीम पर पथराव कर दिया और कर्मचारियों को खदेड़ दिया। घटना ठाकुरद्वारा कोतवाली क्षेत्र के बलिया बहापुर गांव में मंगलवार दोपहर 3 बजे हुई। ठाकुरद्वारा कोतवाली क्षेत्र के बलिया बहापुर गांव की ब्रह्मो देवी पशुओं के लिए चारा लेने खेत गई थीं। क्षेत्र में तेंदुए के लगातार हमलों को देखते हुए करीब 20 महिलाएं एक साथ खेतों पर पहुंची थीं, ताकि समूह में रहकर चारा काट सकें। महिलाएं खेत में चारा काट रही थीं। इसी दौरान गन्ने के खेत से निकले तेंदुए ने ब्रह्मो देवी पर हमला कर दिया।

फास्ट न्यूज

अलीगढ़ में 20 दुकानदारों को नोटिस

अलीगढ़। अलीगढ़ में मुजम्मिल कॉम्प्लेक्स में सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम की स्वच्छ भारत मिशन (SBM) टीम ने सोमवार शाम औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कचरा निस्तारण में लापरवाही और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (SWM) नियमों का पालन नहीं होने पर 20 दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए। टीम ने कॉम्प्लेक्स में संचालित क्लिनिक, फार्मेसी, पैथ लैब, डायग्नोस्टिक सेंटर, डेंटल और आई केयर सेंटर समेत कई प्रतिष्ठानों की जांच की।

शराब की दुकान के विरोध में उतरे स्कूली बच्चे

बोले- माहौल खराब हो रहा, मुरादाबाद डीएम ने कहा- जांच कर ठेका बंद कराएंगे

तमसा संकेत, एजेंसी

मुरादाबाद। मुरादाबाद में मंगलवार को रिहायशी इलाके में खुली शराब की दुकान के विरोध में स्कूली छात्र-छात्राओं और स्थानीय महिलाओं ने प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर-बैनर लेकर बच्चे सड़क पर उतर आए और शराब की दुकान बंद कराने की मांग को लेकर नारेबाजी की। हंगामे की सूचना पर डीएम डॉ. राजेंद्र पेंसिया पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही डीएम डॉ. राजेंद्र पेंसिया भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। बच्चों और महिलाओं की भीड़ को देखते हुए डीएम ने खुद लाउडस्पीकर संभाला और प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया। उन्होंने लोगों की शिकायतें सुनीं और मामले को



गंभीरता से लेने का भरोसा दिया। डीएम ने आबकारी विभाग के अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया। जिला आबकारी अधिकारी रविंद्र प्रताप सिंह ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। मझोला थाना प्रभारी रविंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात रहा। मंडी समिति चौकी प्रभारी आनंदपाल सिंह भी प्रशासनिक टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे। डीएम और आबकारी विभाग के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया कि शराब की दुकान को लेकर मिली शिकायतों की नियमानुसार जांच कराई जाएगी। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के आश्वासन के बाद बच्चे और महिलाएं शांत हुए और प्रदर्शन समाप्त कर दिया। डीएम डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।

बच्चों के हाथों में पोस्टर, शराब की दुकान हटाने की मांग

मामला मझोला थाना क्षेत्र की एकता कॉलोनी का है। मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे और महिलाएं शराब की दुकान के विरोध में सड़क पर उतर आए। बच्चों ने हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में स्कूल के शिक्षक और बच्चों के पैरेंट्स भी शामिल हुए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में शराब की दुकान होने से आए दिन असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। महिलाओं ने कहा कि शराब की दुकान के कारण उन्हें और बच्चियों को घर से निकलने में परेशानी होती है। इससे इलाके का माहौल भी खराब हो रहा है।

मथुरा कलेक्ट्रेट के सामने आधा किमी लंबा जाम

अफसरों की गाड़ियां भी फंसीं, सायरन बजाते रहे

तमसा संकेत, एजेंसी

मथुरा। मथुरा शहर में जाम की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट के सामने भीषण जाम लग गया। देखते ही देखते करीब आधा किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई। जाम में स्थानीय लोगों के साथ बाहर से आए श्रद्धालु और अधिकारियों के वाहन भी फंस गए। गर्मी के बीच काफी देर तक वाहन रेंगते रहे। कलेक्ट्रेट के सामने लगे जाम में कई अधिकारियों के वाहन भी फंस गए। कुछ अधिकारियों ने अपनी गाड़ियों के सायरन बजाए, लेकिन जाम इतना लंबा था कि उन्हें भी काफी देर तक निकलने का रास्ता नहीं मिला। सड़क पर वाहनों की लंबी



कतार के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कलेक्ट्रेट के अलावा भूतेश्वर तिराहा, नया बस स्टैंड और गोवर्धन चौराहा जैसे प्रमुख स्थानों पर भी आए दिन जाम की स्थिति बन रही है। इन इलाकों में वाहनों का दबाव ज्यादा रहता है। इसके साथ ही सड़क किनारे बेतरतीब तरीके से खड़े वाहन यातायात की समस्या को और बढ़ा देते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मुख्य मार्गों के किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनों के खिलाफ यातायात पुलिस और संबंधित विभाग प्रभावी कार्रवाई नहीं करते। सड़क का एक हिस्सा पार्किंग में इस्तेमाल होने से वाहनों के निकलने की जगह कम हो जाती है। इसके चलते यातायात धीमा पड़ता है और कुछ ही देर में लंबा जाम लग जाता है। मथुरा में रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में शहर के प्रमुख मार्गों पर लगने वाला जाम स्थानीय लोगों के साथ श्रद्धालुओं के लिए भी परेशानी का कारण बन रहा है। लोगों ने सड़क किनारे खड़े वाहनों पर कार्रवाई करने, प्रमुख चौराहों पर यातायात पुलिस की तैनाती बढ़ाने और यातायात व्यवस्था को बेहतर करने की मांग की है।

मुरादाबाद में 4 किमी लंबा जाम लगा

मुरादाबाद। मुरादाबाद के लाकड़ी चौराहे पर सोमवार रात यातायात व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ गई। साईं अस्पताल से जीरो प्वाइंट तक करीब 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लगने से गाड़ियां घंटों तक रेंगती रहीं। जाम में मरीजों को लेकर आ रही एंबुलेंस भी फंस गईं। एंबुलेंस के सायरन लगातार बजते रहे, लेकिन वाहनों की भीड़ के कारण उन्हें निकलने के लिए रास्ता नहीं मिल सका। जाम के चलते मरीजों के तीमारदारों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई लोग अपने वाहनों से उतरकर रास्ता खुलवाने की कोशिश करते नजर आए।

जमीन हमारी है, एक इंच नहीं देंगे : महेंद्र प्रताप

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद, तीसरी बार बैठक में नहीं पहुंचा मुस्लिम पक्ष

तमसा संकेत, एजेंसी

मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद मामले में मंगलवार को समझौते की कोशिश एक बार फिर नाकाम रही। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर विशेष लोक अदालत में तीसरी बार समझौते को लेकर बातचीत होनी थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार यादव (द्वितीय) की अदालत में हुई बैठक में हिंदू पक्ष के लोग पहुंचे, लेकिन मुस्लिम पक्ष नहीं पहुंचा। इसके बाद बातचीत की फाइल बंद कर दी गई। अब 21, 22 या 23 अगस्त में से किसी एक दिन सुप्रीम कोर्ट में अगली समझौता बैठक होने की बात कही जा रही है। बैठक के बाद हिंदू पक्ष के वकील महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मुस्लिम पक्ष का बार-बार बैठक में नहीं आना मामले को लटकाने जैसा है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि की करीब ढाई एकड़ जमीन भगवान



श्रीकृष्ण की है। इसके बदले किसी दूसरी जगह जमीन लेने या देने की बात स्वीकार नहीं की जाएगी। महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा- हमारे गोविंद की जमीन के बदले दूसरी जमीन देने वाले हम कौन होते हैं। जमीन हमारी है, इसलिए एक इंच जमीन भी नहीं देंगे। महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि हिंदू पक्ष का मानना है कि वर्ष 1670 में औरंगजेब के समय श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मंदिर को तोड़ा गया और वहां ईदगाह बनाई गई। उन्होंने कहा कि इसी जमीन को लेकर हिंदू पक्ष छह साल से ज्यादा समय से कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा है।

किशोरी से दुष्कर्म करने वाला गिरफ्तार

मथुरा। मथुरा के रिफाइनरी थाना क्षेत्र में 13 साल की किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने 72 वर्षीय विशम्भर दयाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सोमवार को आरोपी को बरेली हाईवे स्थित बाद पुल अंडरपास के नीचे से पकड़ा। शाम को न्यायालय में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी साउथ सिटी पुष्पांजलि कॉलोनी का रहने वाला है।

बीसीआई की मंजूरी का इंतजार, छात्रों को सता रहा साल खराब होने का डर

आगरा कॉलेज में एलएलबी-बीए एलएलबी के एडमिशन अटके

तमसा संकेत, एजेंसी

आगरा। आगरा कॉलेज में लॉ की पढ़ाई की इच्छा रखने वाले छात्रों का इंतजार बढ़ता जा रहा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) से जरूरी अनुमोदन नहीं मिलने के कारण सत्र 2026-27 में बीए-एलएलबी और एलएलबी की प्रवेश प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो सकी है। मंगलवार को छात्र और अभिभावक जानकारी के लिए कॉलेज पहुंचते रहे, लेकिन उन्हें प्रवेश की कोई निश्चित तारीख नहीं मिल सकी। कॉलेज की ओर से सिर्फ जल्द प्रक्रिया शुरू होने की बात कही जा रही है। प्रवेश में देरी से छात्र असमंजस में हैं और उन्हें सत्र पिछड़ने का डर सताने लगा है। आगरा कॉलेज विधि संकाय के



प्रोफेसर गौरव कौशिक ने बताया कि विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया का आवश्यक अनुमोदन जरूरी है। कॉलेज की ओर से पिछले महीने इसके लिए पत्र भेजा जा चुका है। बीसीआई से अनुमति मिलते ही

"एलएलबी में प्रवेश के इच्छुक अंकित ने बताया कि वह भी कई बार कॉलेज के चक्कर लगा चुके हैं। पहले अगस्त में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने की बात कही गई थी। अब सिर्फ जल्द शुरू होने की जानकारी दी जा रही है। अंकित ने कहा कि दूसरी जगह भी प्रवेश की स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे में लगातार इंतजार करना पड़ रहा है। डर है कि कहीं प्रवेश में देरी के कारण पूरा साल खराब न हो जाए।"



विधि संकाय की प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं, बच्चे कॉलेज के लगा रहे चक्कर

कई बार आ चुके कॉलेज, फिर भी तारीख नहीं मिली

बीए-एलएलबी में प्रवेश लेने पहुंचे ओम ने बताया कि वह पहले भी कई बार कॉलेज आकर प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी ले चुके हैं। हर बार जल्द प्रवेश शुरू होने की बात कही जा रही है, लेकिन तारीख नहीं बताई जा रही। उन्होंने कहा कि प्रवेश कब शुरू होगा, इसकी जानकारी नहीं होने से असमंजस बना हुआ है।

सुबह से कॉलेज पहुंचते रहे छात्र

मंगलवार सुबह से ही आगरा कॉलेज के विधि संकाय में छात्र और अभिभावक जानकारी लेने पहुंचते रहे। बीए-एलएलबी के पांच वर्षीय और एलएलबी के तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों की सबसे बड़ी जिज्ञासा यही थी कि आवेदन के लिए पोर्टल कब खुलेगा। कॉलेज स्टाफ से जानकारी लेने पर छात्रों को कोई निश्चित तारीख नहीं मिल सकी। उन्हें बताया गया कि बीसीआई से अनुमोदन मिलते ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

पृष्ठ 01 का शेष...

स्योगी का ऐलान...

योगी ने कहा- आज यूपी बीमारू नहीं रहा। विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। हमने यहां की अर्थव्यवस्था को तीन गुना कर दिया है। योगी ने कहा- पिछली सरकारों का विकास केवल सैफई सिंडिकेट के विकास तक सीमित था। उनका विकास हो और बाकी भाड़ में जाएं। इसलिए वे गुंडागर्दी कराते थे। पहले पीआरडी जवानों को ड्यूटी नहीं मिलती थी। आज पीआरडी के जवान कम पड़ जाते हैं। कोई काम नहीं है तो उन्हें ट्रैफिक में लगाइए, मेट्रो की सुरक्षा का दायित्व दीजिए। पेट से कोई सीखकर नहीं आता, उसे ट्रेनिंग देनी होगी। ट्रेनिंग मिलेगी तो वह अच्छा काम करेगा और परिणाम देगा। CM योगी ने कहा- पीआरडी जवानों को सुविधा मिली है तो उन्हें और बेहतर ढंग से काम करना होगा। हम सब भारतवासियों का एक ही लक्ष्य होना चाहिए। वह है 'देश प्रथम'। जो बांटने का काम करते हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। CM योगी ने कहा- आरोप-प्रत्यारोप वही करते हैं जो कुछ कर नहीं पाते। उन्हें लगता है कि हम कर नहीं सके, इन्होंने कैसे कर दिया। यही उनकी समस्या है। वे माफिया के आगे घुटने टेक देते थे। माफिया को प्रशय देकर उत्तर प्रदेश को बीमारू प्रदेश बना दिया। यहां क्या नहीं था, सबकुछ था। उर्वरा भूमि, सबसे अच्छे प्रगतिशील किसान, पढ़ी-लिखी बेटी, अच्छे व्यापारी, प्रतिभाशली युवा थे, तब भी यूपी बीमार हो गया था। जिन्होंने प्रदेश को बीमार बना दिया, वे यहां के लोगों का इलाज क्या कर पाते। CM योगी ने कहा- जनता तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है तो हमें अपने जवानों को भी सम्मान देना होगा। सबने मिलकर प्रयास किया तो परिवर्तन भी हुआ। यही वह प्रदेश है, जहां रोज दंगे होते थे। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। न आवागमन के साधन थे। अव्यवस्था चारों ओर थी। CM योगी ने कहा-पिछली सरकारों का विकास केवल सैफई सिंडिकेट के विकास तक सीमित था। उनका विकास हो और बाकी भाड़ में जाएं। इसलिए वे गुंडागर्दी कराते थे, लूटपाट कराते थे। CM योगी ने कहा- पहले आपको ड्यूटी नहीं मिलती थी। आज पीआरडी के जवान कम पड़ जाते हैं। कोई काम नहीं है तो उन्हें ट्रैफिक में लगाइए, मेट्रो की सुरक्षा का दायित्व दीजिए, विभिन्न कार्यालयों की सुरक्षा का दायित्व दीजिए, पैमाइश करने के लिए, औद्योगिक संस्थानों की सुरक्षा का दायित्व दीजिए। उसकी ट्रेनिंग हो, समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएं। पेट से कोई सीखकर नहीं आता, उसे ट्रेनिंग देनी होगी। ट्रेनिंग मिलेगी तो वह अच्छा काम करेगा और परिणाम देगा। आज जो प्रगति हुई है वह सामूहिक प्रयास का नतीजा है। सीएम ने कहा- पीआरडी के स्वयंसेवकों का ड्यूटी भत्ता 2019 तक केवल 250 रुपए मिलते थे। 2019 में मैंने इसे बढ़ाकर 375 रुपए किया था। 2022 में इसे बढ़ाकर 395 किया। 2025 में बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया था। अब इसे बढ़ाकर 600 रुपए करने जा रहे हैं। CM योगी ने कहा- यह चीजें बताती हैं कि परिवर्तन किसी एक तबके लिए नहीं है बल्कि हर तबके लिए है और वह दिखाई दे रहा है। आज आपके लिए हम विशेष प्रयोजन से आए हैं।

सोनिया गांधी ने पीएम...

दोनों ने बाद में शादी की और सोनिया ने नेहरू-गांधी परिवार में अपनी जिंदगी शुरू की। इस किताब के मुताबिक, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। इसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, लेकिन 1991 में राजीव गांधी की भी हत्या कर दी गई। सोनिया बाद में सक्रिय राजनीति में आईं और लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं। उनके मुताबिक, किताब उनके जीवन के साथ-साथ भारत में करीब छह दशकों के दौरान हुए सामाजिक और राजनीतिक बदलावों को देखने का एक अलग नजरिया भी देती है। जब मैंने राजनीति से कुछ दूरी बनाकर पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखा, तो मुझे अपनी कहानी में प्यार और वफादारी का एक धागा साफ नजर आया। यह धागा इटली के एक छोटे शहर में बिताए साधारण बचपन से शुरू होकर भारत में राजीव गांधी की पत्नी और इंदिरा गांधी की बहू के रूप में बिताए तक जाता है।

सुप्रीम कोर्ट में फांसी...

इसकी जगह जहरीले इंजेक्शन, गोली मारने जैसे चार वैकल्पिक तरीकों से मौत की सजा देने की मांग की गई थी वरिष्ठ वकील ऋषि मल्होत्रा ने 2017 में यह याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया था कि फांसी की प्रक्रिया में 40 मिनट से ज्यादा लग सकते हैं, जबकि गोली मारने में कुछ मिनट और जहरीले इंजेक्शन में करीब 5 मिनट लगने का दावा किया गया। याचिका में CrPC की धारा 354(5) को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई थी। इसी धारा के तहत मौत की सजा पाए दोषी को गर्दन से तब तक लटकाया जाता है, जब तक उसकी मौत न हो जाए। याचिकाकर्ता ने इसे संविधान के अनुच्छेद 21 में मिले जीवन और गरिमा के अधिकार के खिलाफ बताया गया। मल्होत्रा ने यह भी कहा था कि मौत की सजा पाए कैदी को फांसी और जहरीले इंजेक्शन में से कोई एक तरीका चुनने का विकल्प मिलना चाहिए। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी से होने वाली पीड़ा, मौत में लगने वाले समय और इससे जुड़ी व्यवस्थाओं पर केंद्र से बेहतर डेटा मांगा था। कोर्ट ने इस मुद्दे की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने पर भी विचार किया था। मई 2023 में अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने बताया था कि उन्होंने मौत की सजा के लिए बेहतर विकल्प की जांच करने वाली विशेषज्ञ समिति बनाने की सिफारिश की है। केंद्र सरकार समिति के सदस्यों पर विचार कर रही थी। धनंजय चटर्जी केस (2004): हेतल पारेख के रेप-हत्या मामले में दोषी धनंजय को 14 अगस्त 2004 को अलीपुर जेल में फांसी दी गई। मानवाधिकार संगठनों और शिक्षाविदों ने मौत की सजा और फांसी के तरीके पर सवाल उठाए।

अमेरिका में भारत...

इस विधेयक में डाक से वोट देने की प्रक्रिया को काफी सीमित करने की बात भी कही गई है। यह विधेयक अमेरिकी प्रतिनिधि सभा से पारित हो चुका है, लेकिन सीनेट में इसे अब तक मंजूरी नहीं मिली है। इस मुद्दे पर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, दोनों पार्टी में मतभेद हैं। ट्रम्प लगातार सेव अमेरिका एक्ट को पास कराने पर जोर देते रहे हैं। उनका दावा है कि इससे चुनावी धोखाधड़ी पर रोक लगेगी। अमेरिका में वोटर ID को लेकर लंबे समय से राजनीतिक बहस चल रही है। इसके समर्थकों का कहना है कि फोटो ID और नागरिकता के दस्तावेज चुनाव की विश्वसनीयता बढ़ाने में मदद करेंगे। वहीं, विरोधियों का तर्क है कि अमेरिका में गैर-नागरिकों का मतदान पहले से प्रतिबंधित है और सख्त दस्तावेजी नियमों के कारण ऐसे मतदाता भी प्रभावित हो सकते हैं, जिनके पास जन्म प्रमाणपत्र या वैध पासपोर्ट जैसे दस्तावेज नहीं हैं। बाइपार्टिसन पॉलिसी सेंटर के अनुसार, अमेरिका में करीब 12% पंजीकृत मतदाताओं के पास आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेजी प्रमाण नहीं हैं। फोटो ID को लेकर विकसित देशों में एक जैसा नियम नहीं है। ब्रिटेन में कुछ चुनावों में मतदान केंद्र पर फोटो ID दिखाना अनिवार्य है, जबकि स्कॉटलैंड और वेल्स के कुछ स्थानीय चुनावों में इसकी जरूरत नहीं होती। कनाडा में पहचान और पता साबित करना जरूरी है, लेकिन इसके लिए सिर्फ फोटो ID ही जरूरी नहीं है। मतदाता एक फोटो ID दे सकता है या दो दूसरे मान्य दस्तावेज दिखा सकता है। ID न होने पर कुछ परिस्थितियों में दूसरा मतदाता उसकी पहचान की पुष्टि भी कर सकता है।

पहले बागी विधायकों...

बेंच 2024 में दायर उद्धव गुट की दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इन याचिकाओं में चुनाव आयोग के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें धनुष-बाण निशान शिंदे गुट को दिया गया था। याचिकाओं में चुनाव आयोग के 17 फरवरी 2023 के उस आदेश को भी चुनौती दी गई है, जिसमें शिंदे गुट को मूल शिवसेना माना गया था।

ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट ने 1,500 डॉलर का जुर्माना लगाया, 12 महीने कार में इंटरलॉक डिवाइस लगाना होगा

डेविड वॉर्नर को शराब पीकर गाड़ी चलाने पर सजा

आदेश

नई दिल्ली। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वॉर्नर को शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में दोषी ठहराया गया है। सिडनी की वॉवेर्ली लोकल कोर्ट ने मंगलवार को उन पर 1,500 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का जुर्माना लगाया। साथ ही उनकी कार में 12 महीने के लिए इंटरलॉक डिवाइस लगाने का आदेश दिया गया है। वॉर्नर को ईस्टर संडे के दिन सिडनी के बाहरी इलाके में रैंडम ब्रेथ टेस्टिंग के दौरान पकड़ा गया था। जांच में उनके ब्लड-अल्कोहल लेवल की रीडिंग 0.104 आई थी, जो कानूनी सीमा से दोगुने से भी ज्यादा थी।

वॉर्नर की कार में 12 महीने के लिए इग्निशन इंटरलॉक डिवाइस लगाया जाएगा। यह एक छोटा उपकरण होता है, जिसे कार के



कोर्ट में सुनवाई के बाद डेविड वॉर्नर मीडिया से बात करते हुए।

डैशबोर्ड में लगाया जाता है। कार स्टार्ट करने से पहले ड्राइवर को इसमें सांस का नमूना देना होता है। डिवाइस सांस में अल्कोहल की मात्रा जांचता है। अगर निर्धारित सीमा से ज्यादा अल्कोहल मिलता है तो कार का इंजन स्टार्ट नहीं होता। कुछ सिस्टम ड्राइविंग के दौरान भी दोबारा सांस का नमूना मांग सकते हैं। 39 साल के वॉर्नर ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 112 टेस्ट और 250 से ज्यादा लिमिटेड ओवर्स इंटरनेशनल मैच खेले हैं। उन्होंने 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था। इसके बाद वे कमेंट्री के साथ-साथ फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भी खेल रहे हैं। वॉर्नर फिलहाल सिडनी थंडर के कप्तान हैं और पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स के लिए भी खेलते हैं।

तीन ग्लास व्हाइट वाइन पीने की बात कबूली

कोर्ट में वॉर्नर ने बताया कि उन्होंने गाड़ी चलाने से पहले तीन ग्लास व्हाइट वाइन पी थी। उन्होंने पिछले महीने मिड-रेंज ड्रिंक ड्राइविंग का आरोप स्वीकार कर लिया था।

कोर्ट में बताया गया कि वॉर्नर ने सड़क किनारे ब्रेथ टेस्टिंग साइट देखकर अपनी कार रोकी और एक महिला यात्री के साथ सीट बदलने की कोशिश की थी।

वकील बोले- मीडिया कवरेज से नुकसान हुआ

वॉर्नर के वकील अवैस अहमद ने कोर्ट में कहा कि इस मामले की खबर दुनियाभर के मीडिया में आई, जिससे वॉर्नर को अतिरिक्त नुकसान उठाना पड़ा।

वकील के मुताबिक, ESPN, अल जजीरा और इंडियन एक्सप्रेस जैसे इंटरनेशनल मीडिया संस्थानों ने भी इस घटना को कवर किया। उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश जैसे देशों में शराब से जुड़ी घटनाओं को लेकर अलग तरह की सामाजिक स्वीकार्यता है, जहां वॉर्नर टी-20 फ्रेंचाइजी लीग्स में खेलने के कमर्शियल अवसर तलाश सकते हैं।



कार में यही डिवाइस इंटरलॉक कहलाती है। इसमें सांस का नमूना देना होता है।

- **जुर्माने के अलावा वॉर्नर की कार में 12 महीने के लिए इंटरलॉक डिवाइस लगाया जाएगा। यह डिवाइस कार को तब स्टार्ट नहीं होने देगा, जब ड्राइवर के सिस्टम में शराब की मात्रा पाई जाएगी।**
- **जज क्लेयर फार्नन ने कहा कि वॉर्नर के दोबारा ऐसा अपराध करने की संभावना कम है, लेकिन न्यू साउथ वेल्स में होने वाली कई सड़क दुर्घटनाओं में शराब पीकर गाड़ी चलाना अब भी एक गंभीर कारण है।**

बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम घोषित

वेदराल्ड बाहर, रेनशॉ की वापसी पहले टेस्ट में मिली थी हार

नई दिल्ली, एजेंसी

ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश के खिलाफ 22 अगस्त से मैके में होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए 13 सदस्यीय टीम में एक बदलाव किया है। पहले टेस्ट में 9 विकेट की हार के बाद ओपनर जैक वेदराल्ड को टीम से बाहर कर दिया गया है।

उनकी जगह मैथ्यू रेनशॉ की वापसी हुई है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने एशेज में सफल रही ट्रैविस हेड और वेदरअल्ड की ओपनिंग जोड़ी को सिर्फ एक टेस्ट बाद तोड़ दिया है।

रेनशॉ को दूसरे टेस्ट में ट्रैविस हेड के साथ ओपनिंग करने का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग ऑर्डर को लेकर अंतिम फैसला नहीं किया है। विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिस भी ओपनिंग के विकल्प हैं। उन्होंने पिछले साल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया XI के लिए इंग्लैंड



लायंस के खिलाफ ओपनिंग करते हुए 40 और नाबाद 125 रन बनाए थे। 30 साल के रेनशॉ ने अपना पिछला टेस्ट 2023 में भारत के खिलाफ दिल्ली में खेला था। उन्होंने पिछले शेफील्ड शील्ड सीजन में 10 पारियों में 3 शतक लगाए और करीब 50 की औसत से रन बनाए थे। मैके के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना में भी उनके नाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में दो शतक हैं।

वेदराल्ड को बांग्लादेश के खिलाफ डार्विन में खेले गए पहले टेस्ट में दोनों पारियों में बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। उन्होंने पहली पारी में 23 और दूसरी पारी में 0 रन बनाए। इसके साथ उनका टेस्ट करियर औसत 20.36 रह गया।

बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप उन्नति जीती, अब लक्ष्य सेन उतरेंगे

डबल्स में 4 भारतीय जोड़ियां खेलेंगी पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी भी जीत चुके

नई दिल्ली, एजेंसी

नई दिल्ली के इंदिरा गांधी (IG) स्टेडियम में चल रही BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत की उन्नति हुड्डा ने जीत के साथ अभियान की शुरुआत की। उन्होंने पहले राउंड में म्यांमार की थेत हमतार थुजार को हराकर अगले दौर में जगह बनाई।

उन्नति के मुकाबले के बाद आज भारत के 5 मुकाबले बाकी हैं। इनमें लक्ष्य सेन मेंस सिंगल्स में उतरेंगे। इसके अलावा भारत की टीमें विमेंस डबल्स में 2 और मिक्स्ड डबल्स में 2 मुकाबले खेलेंगी।

भारत ने टूर्नामेंट के पहले दिन अच्छी शुरुआत की थी। पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और डबल्स की तीन जोड़ियां अपने-अपने मुकाबले जीतकर अगले राउंड में पहुंच चुकी हैं। लक्ष्य सेन राउंड ऑफ 64 में रोमानिया के कॉलिन्स फिलिमोन से



भिड़ेंगे। टूर्नामेंट में लक्ष्य का यह पहला मुकाबला होगा। लक्ष्य अटैकिंग गेम के दम पर जीत के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। विमेंस सिंगल्स में उन्नति हुड्डा का मुकाबला म्यांमार की थुजार थेट हार तिन से होगा। यह भी राउंड ऑफ 64 का मुकाबला है।

मिक्स्ड डबल्स में के राउंड ऑफ 64 में भारत की 2 जोड़ियां खेलेंगी। रोहन कपूर और रुत्विका शिवानी गड्डे के सामने कनाडा के जोनाथन बिंग त्सान लाई और क्रिस्टल लाई होंगे।

वहीं दूसरे मुकाबले में अशिथ सूर्य और अमृता प्रमुथेश का मुकाबला तुर्किये के एम्रे सोनमेज और यासेमेन बेक्तास से होगा। विमेंस डबल्स के दोनों मुकाबले राउंड ऑफ 32 में खेले जाएंगे। कविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी राउंड ऑफ 32 में बुल्गारिया की गैब्रिएला स्टोएवा और स्टेफानी स्टोएवा से भिड़ेगी।

दूसरे मैच में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी अमेरिका की लॉरेन लैम और एलिसन ली से खेलेगी। भारत के लिए टूर्नामेंट का पहला दिन बेहद खास रहा। आयुष शेट्टी ने वर्ल्ड नंबर-1 और डिफेंडिंग चैंपियन चीन के शी यू ची को 21-14, 13-21, 21-19 से हराकर बड़ा उलटफेर किया।

दिव्या देशमुख-गायत्री गोपीचंद समेत 17 खिलाड़ियों को अर्जुन अवॉर्ड

12 साल में पहली बार खेल रत्न किसी को नहीं



नई दिल्ली, एजेंसी



खेल मंत्रालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 का ऐलान कर दिया है। 12 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी खिलाड़ी को खेल रत्न नहीं दिया गया हो। इससे पहले 2014 में ऐसा हुआ था। इस साल 17 खिलाड़ियों को अर्जुन अवॉर्ड के लिए चुना गया है। इनमें चेस खिलाड़ी दिव्या देशमुख, विदित गुजराती, एथलीट तेजस्विन शंकर और बैडमिंटन खिलाड़ी गायत्री गोपीचंद व तृषा जॉली जैसे नाम शामिल हैं। फुटबॉल के दिग्गज 84 साल के आई. अरुमायनायगम को अर्जुन अवॉर्ड की लाइफटाइम कैटेगरी में चुना गया है। वे 1962 के जकार्ता एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। चेस में दिव्या देशमुख और विदित



त्रिसा जॉली-गायत्री गोपीचंद ने 2025 में जीता था सैयद मोदी इंटरनेशनल का महिला डबल्स खिताब

बैडमिंटन में गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली को अर्जुन अवॉर्ड के लिए चुना गया है। दोनों महिला डबल्स में भारत की प्रमुख खिलाड़ियों में रही हैं।

तेजस्विन शंकर भी सूची में

एथलेटिक्स में तेजस्विन शंकर को अर्जुन अवॉर्ड दिया जाएगा। वह हाई जंप के साथ डेकाथलॉन में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में डेकाथलॉन में मेडल जीतकर उन्होंने इतिहास बनाया था।

गुजराती को अर्जुन अवॉर्ड के लिए चुना गया है। दिव्या ने 2025 में FIDE विमेंस वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। वह भारत की प्रमुख महिला चेस खिलाड़ियों में शामिल हैं।

मनोरंजन

शाहरुख के घर मन्नत में दो सांप दिखे

रेस्क्यू टीम ने एक पकड़ा, करीब 8 फीट लंबा था, दूसरे की तलाश हो रही

नई दिल्ली। शाहरुख खान के मुंबई स्थित मशहूर बंगले मन्नत में 17 अगस्त को लॉन में दो सांप दिखे। सुरक्षा के मद्देनजर तुरंत रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। टीम ने एक सांप पकड़ लिया है, हालांकि दूसरा सांप अब भी बंगले में ही है।

रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार रात करीब 8 बजे एक स्नेक रेस्क्यूअर को मन्नत के अंदर दो सांप दिखने की जानकारी दी गई। इसके बाद बंगले में तलाशी शुरू की गई, जिसमें एक सांप को सुरक्षित पकड़ लिया गया।

रेस्क्यू किए गए सांप की लंबाई करीब 8 फीट थी। उसकी पहचान धामन के रूप में हुई, जिसे इंडियन रैट स्नेक भी कहा जाता है। यह सांप गैर-जहरीला होता है और बंगले के परिसर में एक सीढ़ी के नीचे छिपा मिला। रेस्क्यू की कोशिश पूरी तरह सफल नहीं रही। परिसर में लोगों की आवाजाही शुरू होने पर दूसरा सांप भाग गया। देर शाम तक उसकी तलाश जारी रही, लेकिन वह नहीं मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सांप के गैर-जहरीला होने की जानकारी मिलने के बाद मन्नत के सिक्योरिटी गार्ड्स और स्टाफ ने राहत महसूस की। शाहरुख ने 1997 में अपनी फिल्म यस बॉस की शूटिंग के दौरान मन्नत को पहली बार देखा। समुद्र के किनारे खड़ा यह बंगला उनकी नजर में बिल्कुल सपनों जैसा था। चुनौती यह थी कि एक सक्सेसफुल एक्टर होने के बावजूद शाहरुख के पास इतने बड़े घर को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे।



मन्नत में नहीं रह रहे हैं शाहरुख खान

शाहरुख खान के बंगले मन्नत में पिछले कुछ महीनों से रेनोवेशन का काम जारी है, जिसके चलते वह अपनी फैमिली के साथ बांद्रा के एक लग्जरी अपार्टमेंट में रह रहे हैं। पाली हिल बांद्रा के चार मंजिला लग्जरी अपार्टमेंट पूजा कासा का किराया हर महीने 24 लाख है। इस अपार्टमेंट में शाहरुख और उनका परिवार अगले 2 साल तक रहेगा। इस लग्जरी अपार्टमेंट को फिल्म प्रोड्यूसर वासु भगनानी ने बनाया है, जिसका मालिकाना हक प्रोड्यूसर के बेटे जैकी भगनानी और बेटी दीपशिखा देशमुख के पास है।



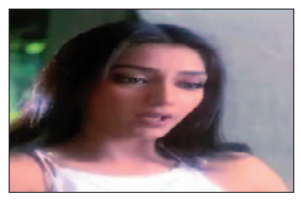


इस बंगले का आधिकारिक नाम मन्नत लैंड्स एंड है। यह मुंबई के बांद्रा इलाके के बैंडस्टैंड में स्थित है। समुद्र के सामने बना शाहरुख का यह घर समय के साथ मुंबई की मशहूर जगहों में शामिल हो गया है। शाहरुख को देखने की उम्मीद में फैंस अक्सर बंगले के बाहर जमा होते हैं।

गुलजार के लिखे गीत पर भड़क गए थे 'पंचम दा'

गुस्से में बना डाला मास्टरपीस गाना

नई दिल्ली। गुलजार साहब ने भारतीय सिनेमा को कई यादगार और कल्ट गाने दिए हैं और जिसने सदाबहार उन्होंने गाने दिए हैं उतने ही मजेदार किस्से उन गीतों के पीछे छुपे हुए हैं। एक ऐसा ही किस्सा है गुलजार साहब के लिखे गाने पर आर डी बर्मन यानी पंचम दा के गुस्सा होने का। ये बात है कुछ 4 दशक पहले की, जब 'पंचम दा' और गुलजार साहब एक फिल्म के लिए एक साथ संगीत तैयार कर रहे थे। तो जब गुलजार साहब (Gulzar) ने एक गीत के लिरिक्स लिखकर दिए तो वे आर डी बर्मन साहब (RD Burman) को बड़े अजीब लगे। क्योंकि उन लिरिक्स में कोई राइमिंग नहीं बैठ रही थी तो पंचम दा ने कहा



कि इसे कैसे कंपोज करूं, इस पर कैसे कोई धुन बनेगी। उन्होंने गुस्से में यह तक कह डाला था कि ऐसे तो कल से किसी अखबार की हेडलाइन ले आओगे। हालांकि कोई और चारा नहीं था तो पंचम दा ने गुस्से में ही इस गाने की धुन तैयार की वो भी सिर्फ 15 मिनट में। कमाल ये था कि गुस्से में बनाये गए इस गाने के लिए गुलजार को लिरिक्स लिखने और आशा भोसले को गायकी के लिए नेशनल अवॉर्ड मिला था।

सुशांत केस के बाद रिया के पिता की नौकरी गई

सरनेम पता चलने पर अस्पताल ने कहा- आप यहां नौकरी नहीं कर सकते, नहीं था कोई रोजगार

नई दिल्ली। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनके परिवार को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 2020 में हुई इस घटना के बाद रिया लगातार लोगों और जांच एजेंसियों की नजर में रहीं। जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो भाई का करियर बर्बाद हो गया और पिता को भी अस्पताल की नौकरी से निकाल दिया गया।

फराह खान के यूट्यूब व्लॉग में रिया ने बताया, 'हमारे पास कोई काम नहीं था, हम घर में बैठे रहते थे। पूरे समाज ने हमें ठुकरा दिया था। फिल्में भी मिल नहीं रही थीं। शौविक को नौकरी भी नहीं मिल रही थी। कोई कॉर्पोरेट उसे लेने को तैयार नहीं थे।'

आगे उन्होंने कहा, 'पापा को शहर के एक बहुत बड़े अस्पताल में मेडिकल सुपरिंटेंडेंट की बहुत बड़ी नौकरी मिली थी। फिर उन्हें उनका सरनेम पता चला और कहा गया- माफ कीजिए, आप रिया चक्रवर्ती के पिता हैं, इसलिए आप यहां काम नहीं कर सकते।' 14 जून 2020 में हुई सुशांत की मौत के बाद रिया जांच के घेरे में आ गई थीं। जांच से जुड़े ड्रग मामले में रिया और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था।

रिया कुछ समय जेल में भी रही थीं। वह पहले बता चुकी हैं कि इस पूरे दौर का उनकी मानसिक सेहत पर असर पड़ा और उन्हें PTSD हुआ था। बाद में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने सुशांत की मौत के मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। इस रिपोर्ट में रिया को मामले के आरोपों से मुक्त किया गया, जिससे उन्हें कई साल की जांच के बाद राहत मिली।



सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया के पिता से भी कई दिन पूछताछ हुई थी।

भाई को मिला आईआईएम में एडमिशन, लेकिन जेल जाने से पढ़ाई छूटी

रिया ने ये भी बताया है कि सुशांत की मौत से पहले उनके भाई शौविक को CAT में 97 प्रतिशत मिले थे और उसका एडमिशन IIM में हुआ था, लेकिन रिया के साथ उनकी भी गिरफ्तारी हो गई। पूरी फीस जमा होने के बावजूद वो पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। रिया ने बताया है कि उन्हें कहीं नौकरी तक नहीं मिली।



ब्रिटिश सरकार वापस पाक भेजने पर अड़ी
30 बच्चों से दुष्कर्म के दोषी पर ब्रिटेन-पाकिस्तान में विवाद

शोषण

लंदन, एजेंसी

ब्रिटेन और पाकिस्तान के बीच एक यौन अपराधी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। शाबिर अहमद ब्रिटेन के कुख्यात ग्रूमिंग गैंग से जुड़ा हुआ है। उसे 30 बच्चों के यौन शोषण का दोषी पाया गया है। शाबिर मूल रूप से पाकिस्तान का रहने वाला है लेकिन उसके पास ब्रिटिश नागरिकता है। अब ब्रिटेन शाबिर को पाकिस्तान भेजना चाहता है, लेकिन इस्लामाबाद ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान ने ब्रिटेन को चेतावनी दी है कि अगर शाबिर को रखने का दबाव बनाया गया, तो वह



ब्रिटेन ने शाबिर अहमद की ब्रिटिश नागरिकता पहले ही खत्म कर दी थी। वहीं, पाकिस्तान का कहना है कि शाबिर ने अपनी पाकिस्तानी नागरिकता भी छोड़ दी थी। ऐसे में इस्लामाबाद का दावा है कि उसे पाकिस्तानी नागरिक नहीं मान सकता।

अवैध प्रवासियों को वापस लेने, सुरक्षा सहयोग और खुफिया जानकारी साझा करने जैसे मुद्दों पर फिर से विचार कर सकता है। ब्रिटेन और पाकिस्तान के बीच 2022 से एक समझौता है। इसके तहत पाकिस्तान अपने उन नागरिकों को वापस लेता है, जिन्हें ब्रिटेन में रहने की अनुमति नहीं है। किसी व्यक्ति को पाकिस्तान वापस भेजने से पहले उसकी पहचान और नागरिकता की पुष्टि की जाती है। इसके बाद पाकिस्तान उसके लिए जरूरी यात्रा दस्तावेज जारी करता है और उसे वापस भेज दिया जाता है। इस समझौते में सिर्फ लोगों को वापस भेजना ही शामिल नहीं है। दोनों देश अवैध प्रवासन, मानव तस्करी और संगठित अपराध से निपटने में भी एक-दूसरे का सहयोग करते हैं। ब्रिटेन और पाकिस्तान के बीच 2022 में हुआ रिटर्न्स समझौते के तहत पाकिस्तान अपने उन नागरिकों को वापस लेता है, जिन्हें ब्रिटेन में रहने का कानूनी अधिकार नहीं है।

इस्लामाबाद ने दी चेतावनी



14 साल जेल की सजा काट चुका शाबिर अहमद

73 वर्षीय शाबिर अहमद पाकिस्तान मूल का है। बच्चों के यौन शोषण मामले में उसे 22 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। वह करीब 14 साल जेल में काट चुका है और हाल ही में रिहा हुआ है। ब्रिटेन उसकी नागरिकता समाप्त कर चुका है और अब उसे पाकिस्तान भेजने की कोशिश कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान का कहना है कि शाबिर ने अपना अधिकांश जीवन ब्रिटेन में बिताया, वहीं उसका पालन-पोषण हुआ और वहीं उसने अपराध किए, इसलिए उसकी जिम्मेदारी भी ब्रिटेन को ही उठानी चाहिए।

वीजा प्रतिबंध की खबरों से भी नाराज पाकिस्तान

ब्रिटेन की कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि अगर पाकिस्तान शाबिर अहमद को वापस लेने से इनकार करता है, तो ब्रिटिश सरकार पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा पर सख्ती कर सकती है। कुछ रिपोर्टों में पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक सहायता घटाने की भी बात कही गई है। हालांकि, ब्रिटेन की ओर से इन कदमों की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने इसे लेकर नाराजगी जताई है। डेली टेलीग्राफ से बातचीत में एक अधिकारी ने कहा कि अगर वीजा और आर्थिक मदद को दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया, तो इससे दोनों देशों के रिश्तों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

बंटवारे के समय जिन्ना की बीमारी को रखा गुप्त

अब मुंबई के दो डॉक्टरों को मिलेगा पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान

इस्लामाबाद, एजेंसी



बॉम्बे (अब मुंबई) के दो भारतीय पारसी डॉक्टरों को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलने वाला है। उन्हें यह सम्मान 1947 में बंटवारे से पहले के अहम समय में पाकिस्तान के संस्थापक मुहम्मद अली जिन्ना की जानलेवा बीमारी की जानकारी को गुप्त रखने के लिए दिया जा रहा है।

इस्लामाबाद ने डॉक्टर जल रतनजी पटेल और रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर जल धायभो-कू को निशान-ए-इम्तियाज अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट किया है। प्लानिंग, डेवलपमेंट और स्पेशल इनिशिएटिव्स के मिनिस्टर और अवॉर्ड कमिटी के हेड अहसान इकबाल ने बताया कि उन्हें यह सम्मान उनकी शांत लेकिन असाधारण सेवा के लिए दिया जा रहा है, जिसके तहत उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि जिन्ना की गंभीर बीमारी की जानकारी सिर्फ उनके करीबी लोगों तक ही सीमित रहे।

एक्स पर एक पोस्ट में अहसान इकबाल ने बताया कि डॉ. पटेल और डॉ. धायभो-कू ने 1946 में जिन्ना के एक्स-रे की जांच की थी और पाया था कि उनकी टीबी की बीमारी काफी बढ़ चुकी थी और उनके पास जीने के लिए बस एक-दो साल ही बचे थे लेकिन उन्होंने उनकी बीमारी की गंभीरता के बारे में पेशेवर गोपनीयता बनाए रखी। एक ऐसा राज जिसके बारे में कई इतिहासकारों का मानना था कि अगर यह पता चल जाता तो बंटवारे और पाकिस्तान के बनने का समय बदल सकता था।

फास्ट न्यूज

'सऊदी अरब में भीख न मांगें'

इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने सऊदी अरब में हज और उमराह के लिए जाने वाले अपने नागरिकों को सख्त चेतावनी दी है। पाकिस्तानी दूतावास ने कहा है कि भीख मांगना, बिना अनुमति पैसे इकट्ठा करना और वीजा नियमों का उल्लंघन न करें, वरना गिरफ्तारी, हिरासत और देश निकाला हो सकता है। सऊदी अरब स्थित पाकिस्तानी दूतावास ने उमराह यात्रियों और मजदूरों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश जारी किया है।

ट्रंप के 57 अधिकारियों की संपत्ति 10 करोड़ डॉलर से अधिक

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने अपने प्रशासन में अत्यधिक अमीर लोगों को शामिल करने के मामले में इतिहास रच दिया है। उपभोक्ता वकालत समूह पब्लिक सिटिजन की सोमवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप द्वारा नियुक्त किए गए 950 करोड़ से अधिक संपत्ति वाले अधिकारियों की संख्या पिछले तीन राष्ट्रपतियों के कुल आंकड़ों से भी चार गुना ज्यादा है। खुद एक अरबपति कारोबारी रहे ट्रंप ने हमेशा से इस फैसले का बचाव किया है, उनका मानना है कि इतनी बड़ी वित्तीय कामयाबी ही किसी व्यक्ति की प्रशासनिक क्षमता और योग्यता का सबसे बड़ा सबूत है।

'भारत में हर वोटर के पास वैलिड आईडी'

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को भारत की चुनाव प्रणाली की तारीफ करते हुए अमेरिका में मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी) अनिवार्य करने की जोरदार वकालत की। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इस महीने की शुरुआत में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हमारे प्रशासन से पूछा आप बिना वैध फोटो आईडी के अमेरिका में चुनाव कैसे करवा सकते हैं?

जेल में बंद इमरान खान को पाक सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

इलाज के लिए अस्पताल भेजने का आदेश

इस्लामाबाद, एजेंसी



पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत देते हुए देश की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जेल से एक प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश दिया है। अदालत का यह फैसला इमरान के गिरते स्वास्थ्य को लेकर उठ रही चिंताओं के बीच आया है।

उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और उनके परिवार के सदस्य काफी समय से उन्हें अस्पताल ले जाने की मांग कर रहे थे, जिसका अदालत ने संज्ञान लिया। पीटीआई के प्रवक्ता नईम हैदर पंजुथा के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इमरान खान को अगले 48 घंटों के भीतर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। अदालत ने कहा है कि इमरान 16 सितंबर तक इसी अस्पताल में भर्ती रहेंगे।

आंखों की रोशनी जाने का खतरा

क्रिकेटर से राजनेता बने 73 वर्षीय इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं। पिछले साल से ही उनके बेटे और परिवार के अन्य सदस्य लगातार उनके बिगड़ते स्वास्थ्य पर चिंता व्यक्त कर रहे थे। इमरान के वकीलों ने दावा किया था कि जेल में रहने के दौरान उनकी दाहिनी आंख की रोशनी काफी कम हो गई है और उन्हें गंभीर चिकित्सा देखभाल की जरूरत है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का PTI ने स्वागत किया है। पार्टी के प्रवक्ता जुल्फिकार बुखारी ने कहा कि यह एक बहुत ही स्वागत योग्य आदेश है।

फिर खुदकुशी की, फायरिंग का वीडियो फेसबुक पर लाइव किया, 2 गार्ड भी मारे गए
फिलीपींस के स्कूल में छात्र ने क्लासमेट को गोली मारी

मनीला, एजेंसी

फिलीपींस के जाम्बोआंगा शहर में मंगलवार को एक स्कूल में गोलीबारी हुई है। एक छात्र ने अपने ही स्कूल के एक दूसरे छात्र को गोली मार दी। इसके बाद उसने खुद भी जान दे दी। फायरिंग में दो सुरक्षा गार्डों की भी मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हुए हैं।

घटना एटेनियो डी जाम्बोआंगा यूनिवर्सिटी के स्कूल कैंपस में हुई। पुलिस का कहना है कि आरोपी छात्र ने हमले का कुछ हिस्सा फेसबुक पर लाइव भी दिखाया था। घटना के बाद स्कूल में हड़कंप मच गया और छात्रों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया।

विभाग ने लोगों से यह भी कहा है कि बिना पुष्टि वाली खबरें,



फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर न करें। इससे पहले जून में ताकलोबान शहर के एक स्कूल में हुई गोलीबारी में 3 छात्रों की मौत हो गई थी और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ताजा घटना के बाद स्कूलों की सुरक्षा और छात्रों तक हथियार पहुंचने को लेकर फिर से सवाल उठने लगे हैं।



फिलीपींस के शिक्षा विभाग ने कहा है कि घटना से प्रभावित छात्रों, परिवारों और स्कूल कर्मचारियों को जरूरी मदद दी जाएगी।

इसके लिए काउंसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि लोग इस सदमे से बाहर निकल सकें।

पहले शिक्षक पर गोली चलाई, फिर छात्र को निशाना बनाया

पुलिस के मुताबिक, आरोपी कक्षा 9 का छात्र मोहम्मद मैल जलानी था। वह दो पिस्तौल लेकर स्कूल आया था। पहले उसने एक टीचर पर गोली चलाई, लेकिन वह बच गए। इसके बाद उसने कक्षा 10 के एक छात्र को गोली मार दी। फिर ऊपर की मंजिल पर गया और वहां से कूदकर जान दे दी। फिलीपींस के गृह मामलों के मंत्री जॉनविक रेमुल्ला ने बताया कि आरोपी सीढ़ियां चढ़ते समय फेसबुक पर लाइव वीडियो बना रहा था।

घटना के बाद स्कूल ने सीनियर हाईस्कूल की क्लास बंद कर दीं। छोटे बच्चों को सुरक्षित रखा गया है और सभी बच्चों की गिनती कर ली गई है। वे अपने टीचर्स के साथ हैं। पुलिस ने बच्चों के माता-पिता से घबराने के बजाय स्कूल की तरफ से दी जा रही जानकारी और निर्देशों का पालन करने को कहा है।

ईरान युद्ध के चलते गिरावट, 80% अमेरिकी बोले- जंग लंबी चलेगी
ट्रम्प की लोकप्रियता घटी सिर्फ 33% लोगों की पसंद

वॉशिंगटन डीसी, एजेंसी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की लोकप्रियता ईरान युद्ध के बीच लगातार घट रही है। रॉयटर्स/इप्सोस के ताजा सर्वे में सिर्फ 33% अमेरिकियों ने ट्रम्प के कामकाज को मंजूरी दी। वहीं 64% लोगों ने उनके कामकाज को नापसंद किया। यह ट्रम्प के मौजूदा राष्ट्रपति कार्यकाल की सबसे कम अप्रूवल रेटिंग है।

इससे पहले इसी महीने हुए सर्वे में ट्रम्प की अप्रूवल रेटिंग 35% थी। मौजूदा 33% की रेटिंग उनके पहले कार्यकाल के दिसंबर 2017 में दर्ज सबसे निचले स्तर के बराबर है।

सर्वे में 80% अमेरिकियों ने कहा कि ईरान के साथ अमेरिका की जंग लंबे समय तक चल सकती है। इनमें



87% डेमोक्रेट और 71% रिपब्लिकन शामिल हैं। सिर्फ 16% लोगों का मानना है कि यह युद्ध कुछ हफ्तों में खत्म हो जाएगा। वहीं केवल 5 में से 1 अमेरिकी का मानना है कि ईरान के खिलाफ युद्ध करना सही फैसला था।

अमेरिका और ईरान के बीच 17 जून को एक समझौता ज्ञापन (MOU) हुआ था। इसके तहत दोनों देशों के बीच बातचीत के लिए 60 दिन का समय तय किया गया था। इस अवधि में कई अहम मुद्दों पर समाधान निकालने की कोशिश की जानी थी। लेकिन 60 दिन पूरे होने के बाद भी प्रमुख मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी। होर्मुज स्ट्रेट खोलने, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और स्थायी शांति समझौते को लेकर दोनों देशों की स्थिति अलग बनी हुई है।

ट्रम्प का ईरान से बातचीत की डेडलाइन बढ़ाने से इनकार

ट्रम्प ने ईरान के साथ शांति वार्ता के लिए तय 60 दिन की समयसीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया है। सोमवार को यह डेडलाइन खत्म हो गई। ट्रम्प ने कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है, लेकिन वह उस तरह की डील के लिए तैयार नहीं है, जिसे अमेरिका जरूरी मानता है।

ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में ट्रम्प ने कहा, "वे समझौता करना चाहते हैं, लेकिन वे उस तरह का समझौता नहीं करने जा रहे, जिसे मैं जरूरी मानता हूं।" अमेरिका की प्रमुख मांग ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना है। वहीं, ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण ऊर्जा के लिए जारी रखने की बात कहता रहा है। यही दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है।

ईरान ने कहा- 60 दिन की डेडलाइन का कोई मतलब नहीं

ईरान ने भी बातचीत की समयसीमा बढ़ाने को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि दोनों देशों के बीच वास्तव में कोई बातचीत शुरू ही नहीं हुई थी। उन्होंने कहा, "हमने कोई बातचीत शुरू ही नहीं की थी और अमेरिका ने शुरुआत से ही समझ को तोड़ दिया। इसलिए 60 दिन का मुद्दा प्रासंगिक नहीं है।"

ईरान का कहना है कि अमेरिका ने समझ के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कीं।

एयरटेल पेमेंट्स बैंक की नई चेयरपर्सन होंगी शबनम सिन्हा

सुनील मित्तल 10 साल बाद पद छोड़ेंगे

नई दिल्ली, एजेंसी



एयरटेल पेमेंट्स बैंक की नई चेयरपर्सन शबनम सिन्हा होंगी। वे 1 अक्टूबर 2026 से यह पद संभालेंगी। शबनम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सुनील भारती मित्तल की जगह लेंगी। मित्तल 30 सितंबर को अपना 10 साल का कार्यकाल पूरा करके बोर्ड से हट जाएंगे। डॉ. शबनम सिन्हा के पास बैंकिंग, गवर्नेंस और डिजिटल बदलाव का 30 से ज्यादा सालों का ग्लोबल अनुभव है। उन्होंने 2010-2025 यानी 15 साल वर्ल्ड बैंक में बतौर लीड स्पेशलिस्ट काम किया। यहां उन्होंने एशिया, यूरोप और अफ्रीका में 4 बिलियन डॉलर यानी करीब 38,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी संभाली।

वर्ल्ड बैंक से पहले वह IL&FS एजुकेशन की CEO रह चुकी हैं और USAID व NCERT के साथ भी लंबे समय तक काम कर चुकी हैं।

फिलहाल वह एयरटेल पेमेंट्स बैंक, वेदांता और भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे बड़े संस्थानों के बोर्ड में शामिल हैं। डॉ. शबनम ने कहा कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक की कमान संभालना मेरे लिए गर्व की बात है, खासकर ऐसे वक्त में जब डिजिटल बैंकिंग देश की तरक्की में सबसे अहम रोल निभा रही है। बैंक ने आसान तकनीक के जरिए एक ऐसा मजबूत और भरोसेमंद जरिया तैयार किया है, जो देश के करोड़ों लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचा रहा है। मैं सुनील मित्तल जी और बोर्ड के इस भरोसे के लिए उनका शुक्रिया अदा करती हूं और बैंक को और आगे ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार हूं।

घटना : पटरियों पर बैठकर गाना गाया, बोला- मुझे अंग्रेजी नहीं आती, ट्रेन सर्विस रोकनी पड़ी

कनाडा के वैंकूवर में ट्रेन ट्रैक पर चढ़ा सिख शख्स

वैंकूवर, एजेंसी

कनाडा के वैंकूवर में एक सिख शख्स के स्काई ट्रेन के ट्रैक पर चले जाने से ट्रेन सेवा रोकनी पड़ी। शख्स काफी देर तक पटरियों पर बैठा रहा और वहां गाना गाता नजर आया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

वायरल वीडियो में शख्स बार-बार "आई डॉन्ट नो इंग्लिश" यानी मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, कहते सुनाई दे रहा है। वीडियो में वह पटरियों पर उछल-कूद करता और गाना गाता भी नजर आ रहा है।

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस-कर्मियों ने शख्स को ट्रैक से बाहर



निकाल लिया। उसे हटाए जाने के दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने तालियां भी बजाईं। इसके बाद पुलिस और ट्रेन कर्मचारी पहले व्यक्ति को ट्रैक से बाहर निकालते हैं। फिर यह जांच की जाती है कि ट्रैक पूरी तरह खाली और सुरक्षित है या नहीं। सुरक्षा की पुष्टि होने के बाद ही ट्रेन सेवा दोबारा शुरू की जाती है। स्काई ट्रेन की कई ट्रेनें एक ही नेटवर्क से जुड़ी होती हैं। इसलिए ट्रैक के किसी एक हिस्से में सुरक्षा से जुड़ी समस्या होने पर उसका असर आसपास चल रही दूसरी ट्रेनों पर भी पड़ सकता है।



शख्स के ट्रैक पर मौजूद होने के कारण स्काई ट्रेन की आवाजाही प्रभावित हुई। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ट्रेन सेवा को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। किस वजह से शख्स ट्रैक पर गया था, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। उसके खिलाफ पुलिस ने क्या कानूनी कार्रवाई की, इसकी भी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

स्काई ट्रेन क्या है और यह कैसे चलती है?

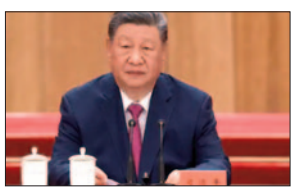
वैंकूवर की स्काई ट्रेन एक तरह की मेट्रो ट्रेन है। इसकी खासियत यह है कि इसे चलाने के लिए ट्रेन में ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती। इसका संचालन कंप्यूटर आधारित स्वचालित सिस्टम से होता है। इसमें संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली ट्रेन की गति, ब्रेक, दिशा और दरवाजों जैसी कई चीजों को नियंत्रित करती है। अगर ट्रैक पर कोई व्यक्ति पहुंच जाए, तो सुरक्षा व्यवस्था के तहत ट्रेन संचालन को नियंत्रित किया जाता है। ऐसी स्थिति में ट्रेन के संचालन से जुड़े सिस्टम और कंट्रोल सेंटर सक्रिय होकर ट्रेनों की आवाजाही को रोकने या नियंत्रित करने में मदद करते हैं। स्काई ट्रेन का बड़ा हिस्सा सड़क के ऊपर बने ट्रैक पर चलता है। कुछ हिस्सों में यह जमीन के नीचे भी जाती है। स्काई ट्रेन के ट्रैक पर आम लोगों का जाना बेहद खतरनाक होता है। ट्रेन के ट्रैक पर किसी व्यक्ति के पहुंचने की जानकारी मिलते ही सुरक्षा के लिए संबंधित हिस्से में ट्रेन की आवाजाही रोक दी जाती है।

शी जिनपिंग ने तियानमेन प्रदर्शन कुचलने को सही ठहराया

बोले- कम्युनिस्ट पार्टी का फैसला सही था

बीजिंग, एजेंसी

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 1989 के तियानमेन प्रदर्शन को रोकने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी की कार्रवाई का समर्थन किया। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन की भी तारीफ की। शी ने कहा कि उस समय जियांग ने पार्टी के फैसले का साथ दिया और शंघाई में हालात को काबू में रखने में अहम भूमिका निभाई। शी ने यह बात सोमवार को पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन की 100वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में कही। उन्होंने चीन के सामने मौजूद चुनौतियों का भी जिक्र किया। शी ने लोगों से मुश्किल वक्त में हार न मानने और हर चुनौती का डटकर सामना करने की अपील की। 1989 में चीन की राजधानी बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पर लोकतांत्रिक सुधारों की मांग को लेकर बड़े प्रदर्शन हुए थे। कई हफ्तों



तक चले इन प्रदर्शनों में हजारों छात्र और आम नागरिक शामिल हुए थे।

इसके बाद चीनी सेना ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग किया और प्रदर्शन को कुचल दिया। कार्रवाई में सेना और टैंकों का इस्तेमाल किया गया था।

इस घटना में कितने लोगों की मौत हुई, इसका कोई पक्का आंकड़ा नहीं है। चीन की सरकार ने 200 से ज्यादा लोगों की मौत की बात कही थी। वहीं, अलग-अलग विदेशी स्रोतों और अनुमानों में मृतकों की संख्या सैकड़ों से लेकर हजारों तक बताई गई है। तियानमेन की यह घटना आज भी चीन में बेहद संवेदनशील मानी जाती है।

तमसा संकेत
tamsa.newslko@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक विद्या देवी द्वारा कृष्णा डाइनेस्टी प्रिंटिंग प्रेस म0 न0 195 सेक्टर 6-बी, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड लखनऊ-226 029 (उ0प्र0) से मुद्रित व प्रकाशित।

सम्पादक : विद्यादेवी

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा

समाचार पत्र में प्रकाशित लेख, राजनीतिक विश्लेषण, लेखकों के अपने विचार हैं। सम्पादक का इन विचारों से सहमत होना आवश्यक नहीं हैं।
मो0- 9415799533
R.N.I. NO. UPHIN/2021/83676